शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 319 | गुवाहाटी | गुरुवार, 25 जून, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

अंबुवासी महायोग में भक्तों की भारी भीड़, साधना में लीन साधक पेज 2
भारत-यूके एफटीए लागू होने से पहले असम और यूके ने सहयोग के रोडमैप पर की चर्चा पेज 3
भगवंत मान अगर सच्चे हैं तो फर्जी रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी : राज्य सभा ... पेज 5
स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए उपलब्ध है नेमार, लेकिन खेलना... पेज 7

अरुणाचल बाढ़ : पांच व्यक्ति लापता

भूस्खलन से पांच जिलों का सड़क संपर्क कटा

इटानगर (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के केयी पान्योर जिले में पोसा में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निपको) प्रोजेक्ट के कॉलोनी के आस-पास के इलाकों में बीती रात से बुधवार सुबह तक लगातार हुई भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार आज दोपहर 3 बजे तक अचानक आई बाढ़ के चलते पांच लोग लापता हैं। निपको प्रोजेक्ट हेड के अनुसार पांच लोगों के लापता होने की सूचना है। इस बीच कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को एम्बुलेंस से जीरो ले जाया गया है। पितापुल में सड़क बंद होने के कारण तीनों घायलों को एम्बुलेंस से आगे ले जाने से पहले, सड़क के बंद हिस्से को पैदल चलकर पार किया गया। कई जगहों पर जबरदस्त भूस्खलन के कारण केयी पान्योर जिले के पोसा, होज और पोटिन इलाकों मे भूस्खलन के कारण लगभग पांच अन्य जिला भी पूरी तरह कट गए हैं। सूत्रों के अनुसार, 23 और 24 जून की रात हुई लगातार बारिश से अचानक बाढ़ आ गई और यजाली सर्कल के तहत निपको प्रोजेक्ट कॉलोनी और उसके पास निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे कॉलोनी के लगभग 20 क्वार्टर क्षतिग्रस्त हो गए और एक निर्माणाधीन रिटेनिंग वॉल बह गई। चार पहिया वाहनों सहित कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। केयी पान्योर की जिला उपायुक्त श्वेता -शेष पृष्ठ दो पर

हाई अलर्ट पर असम

गुवाहाटी (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में हुई भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से पैदा हो रही स्थिति पर असम सरकार बारीकी से नजर रख रही है। माना जा रहा है कि इसका असर असम के कई जिलों पर भी पड़ेगा। गुवाहाटी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) और इटानगर के मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, निचले सुबनसिरी जिले के यजाली स्टेशन पर पिछले 24 घंटों में लगभग 72.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसमें से ज़्यादातर बारिश 24 जून को सुबह 06:00 बजे से 09:00 बजे के बीच हुई। सैटेलाइट और रडार की तस्वीरों से पता चलता है कि सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अचानक बाढ़ आ गई और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में नदियों के बहाव में भारी बढ़ोतरी हुई। पन्योर लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (जिसे पहले रंगानदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था) वाले इलाके में अचानक बाढ़ आने की खबर है। पानी के बहाव में अचानक बढ़ोतरी के कारण, ऑपरेशनल उपाय किए गए और अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए एक स्पिलवे गेट खोला गया। यजाली से मिली खबरों के मुताबिक, अचानक आई बाढ़ और मलबे के बहाव से प्रभावित इलाकों में घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते बहाव को देखते हुए, असम के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर और बहाव की गति में काफी बढ़ोतरी की आशंका है। बाढ़ की लहर के सबसे पहले धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और शोणितपुर जैसे जिलों को प्रभावित करने की उम्मीद है। इसके बाद यह अन्य जिलों से होते हुए आगे बढ़ेगी और अगले एक-दो दिनों में धुबड़ी तक पहुंच जाएगी। राज्य में इस स्थिति पर सबसे उच्च स्तर पर नजर रखी जा रही है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के निर्देश पर, असम के मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से बात की है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने और सभी जरूरी तैयारी के उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संभावित रूप से प्रभावित जिलों -शेष पृष्ठ दो पर

नए एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर के जरिए छह घंटे की यात्रा सीमा हासिल करना असम का लक्ष्य : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य पूर्वोत्तर में यात्रा के समय को काफी कम करने और क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर का एक नेटवर्क बना रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य असम के हर क्षेत्र को छह घंटे की यात्रा दूरी के भीतर लाना है, जिससे यात्रा की अवधि में काफी कमी आएगी जो वर्तमान में 13 से 15 घंटे के बीच है। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में से एक पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जो सिलीगुड़ी-सिलचर एक्सप्रेसवे की व्यापक परिकल्पना का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिलांग-सिलचर कॉरिडोर को लगभग 22,864 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 166.8 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की परिकल्पना की -शेष पृष्ठ दो पर

असम के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में आने वाला है अभूतपूर्व बदलाव : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और जोर दिया कि चल रहे परिवर्तन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना और राज्य के लोगों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण करना है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम में स्वास्थ्य सेवा में बदलाव का मतलब सिर्फ अस्पताल बनाना नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के निर्माण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चिकित्सा अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है और विभिन्न जिलों में कई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल विकसित किए -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

बोड़ो शांति समझौते के कार्यान्वयन में देरी को लेकर आब्सू ने केंद्र और असम सरकार को चेताया

कोकराझाड़। ऑल बोड़ो स्टूडेंट्स यूनियन (आब्सू) ने केंद्र और असम दोनों सरकारों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए तीसरे बोड़ो शांति समझौते के कार्यान्वयन में तत्काल तेजी लाने की मांग की है। 27 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौते के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक, इस छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि लगातार देरी से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क सकते हैं और समुदाय को *विकास की स्वतंत्रता* पर केंद्रित रणनीति की ओर धकेल सकते हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए, आब्सू नेतृत्व ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसके महत्वपूर्ण मूल प्रावधान अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उनकी प्रमुख शिकायतों में बोड़ोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) को मजबूत करने में देरी, आदिवासी भूमि अधिकारों के लिए -शेष पृष्ठ दो पर

असम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस और एसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला

गुवाहाटी। असम सरकार ने 24 जून को राज्य की नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें कई वरिष्ठ आईएएस और एसीएस अधिकारियों को प्रमुख विभागों और जिला प्रशासनों में स्थानांतरित और पुन: नियुक्त किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आईएएस अधिकारी सैयदैन अब्बासी, जो वर्तमान में लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और जल संसाधन विभागों के विशेष मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को आवास और शहरी मामलों के विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें सिंचाई विभाग के विशेष मुख्य सचिव के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। समग्र शिक्षा असम मिशन के प्रबंध निदेशक डॉ. ओम प्रकाश को असम सरकार में पर्यावरण एवं वन एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभागों में आयुक्त और सचिव नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय परिवर्तनों में, होजाई जिले के आयुक्त देबो प्रसाद मिश्रा को गृह और राजनीतिक विभाग में सचिव के रूप में तैनात किया गया है, जबकि चिरांग जिले के आयुक्त मधुसूदन नाथ को कृषि विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। धुबड़ी जिले की आयुक्त मेघा निधि दहल का तबादला वित्त विभाग में सचिव के रूप में कर दिया गया है और उन्हें -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए।

– आचार्य चाणक्य

तारातला में निर्माणाधीन गोदाम की छत ढही, तीन की मौत

कोलकाता (हि.स.)। कोलकाता के तारातला इलाके में ब्रेस ब्रिज के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। बुधवार को तीन मंजिला निर्माणाधीन चाय गोदाम की तीसरी मंजिल की छत की ढलाई के दौरान अचानक ढांचा भरभराकर गिर पड़ा। मलबे के नीचे कई मजदूर दब गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि अब तक 18 घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घटना के बाद सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, कोलकाता पुलिस, अग्निशमन विभाग और -शेष पृष्ठ दो पर

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं ट्रैवल डॉक्यूमेंट : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। अगर आप पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत समझते हैं तो विदेश मंत्रालय का ताजा बयान पढ़ लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने दो टूक कहा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं दी गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन को छोड़कर, पासपोर्ट के लिए छह कामकाजी दिन लगते हैं। पीएसके (पासपोर्ट सेवा केंद्र) और पीओपीएसके (डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र) में 45 मिनट से भी कम समय लगता है। देश भर में 545 पासपोर्ट केंद्र हैं। जबकि 10 साल पहले सिर्फ 77 पासपोर्ट केंद्र थे। केंद्रों की संख्या में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। हमने पिछले -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तान की चर्चित एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्रकैद, मचा बवाल

नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की चर्चित एक्टिविस्ट महरंग बलोच को क्वेटा की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2024 में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक अर्धसैनिक जवान की हत्या और आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया। महरंग बलोच मार्च 2025 से हिरासत में हैं। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है। क्वेटा की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने महरंग बलोच और उनके सहयोगी सिबगतुल्लाह को हत्या तथा आतंकवाद से जुड़े अपराधों में दोषी पाया। कोर्ट के अनुसार जुलाई 2024 में ग्वादर में हुए एक -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

पाक एयरस्पेस में घुसा एयर इंडिया का विमान, मचा हड़कंप

नई दिल्ली। एयरलाइन ने बताया कि 22 जून को दिल्ली से पंजाब के अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट, अमृतसर एयरपोर्ट पर *गो-अराउंड* प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चली गई थी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि फ्लाइट एआई479 के क्रू ने उड़ान के दौरान पाकिस्तान -शेष पृष्ठ दो पर

लोस अध्यक्ष से मिले शिवसेना उद्धव गुट के नेता

नई दिल्ली (हि.स.)। शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने अध्यक्ष के समक्ष पार्टी से अलग हुए सांसदों के संबंध में अपना पक्ष रखा और अनुरोध किया कि अध्यक्ष उनकी ओर से -शेष पृष्ठ दो पर

लोकतंत्र में पद सेवा का माध्यम विशेषाधिकार का नहीं : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली (हि.स.)। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति नागरिकों और सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों के बीच विश्वासपूर्ण संबंध में निहित है तथा सार्वजनिक पद को विशेषाधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति भवन में पूर्व राज्यसभा सदस्य नबाम रेबिया और सह-लेखक संदीप कुमार द्वारा लिखित पुस्तक *भारत में वीआईपी संस्कृति : सत्ता, विशेषाधिकार और लोकतंत्र से दूरी* के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय संविधान न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज की परिकल्पना करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब सार्वजनिक जीवन में विनम्रता, जवाबदेही और जनसेवा की भावना को प्राथमिकता दी जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र का सार नागरिकों और सार्वजनिक प्राधिकार से जुड़े लोगों के बीच संबंधों में निहित है। उन्होंने महान तमिल संत-कवि तिरुवल्लुवर का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चे नेतृत्व की पहचान -शेष पृष्ठ दो पर

एआई इंसानों से सीख रहा भेदभाव और नस्लवाद : यूएन रिपोर्ट

नई दिल्ली। हम अक्सर सुनते हैं कि एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि कुछ मामलों एआई ने इंसानों के कुछ सबसे बुरे भेदभाव करने के तरीके भी अपना लिए हैं। एक रिसर्चर्स ने 133 एआई सिस्टम की स्टडी की और पाया कि लगभग आधे (44 प्रतिशत) सिस्टम में जेंडर के आधार पर भेदभाव (जेंडर बायस) था, जबकि एक-चौथाई से ज्यादा में जेंडर और नस्ल दोनों के आधार पर भेदभाव देखा गया। एनडीटीवी के अनुसार, लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएमएस) ने बार-बार महिलाओं को घर परिवार और बच्चों की देखभाल से जोड़ा है, जबकि पुरुषों को बिजनेस, लीडरशिप और करियर में सफलता से जोड़ा है। यूएन ने कहा कि कुछ मामलों में एआई सिस्टम ने ऐसे जवाब दिए हैं जिनमें महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट या पुरुषों के अधीन दिखाया गया है। यूएन विमेन के अनुसार, जब रिसर्चर्स ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से किसी व्यक्ति के जेंडर से शुरू होने वाले वाक्य को पूरा करने के लिए कहा कि तो हर 5 में से लगभग एक जवाब भेदभावपूर्ण -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

अंबुवासी महायोग में भक्तों की भारी भीड़, साधना में लीन साधक

गुवाहाटी (हि.स.)। विश्व के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक श्री कामाख्या मंदिर में 22 जून से पांच दिवसीय कार्यक्रमों के साथ आरंभ हुआ अंबुवासी महायोग के मद्देनजर नीलांचल पहाड़ पर श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति देखी जा रही है। 22 जून की रात 9 बजकर 8 मिनट 42 सेकंड पर अंबुवासी प्रवृत्ति प्रारंभ होने से पूर्व सभी नित्य पूजा-अर्चना संपन्न कर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु तीन दिनों के लिए बंद कर दिए गए। परंपरा के अनुसार 26 जून की सुबह देवी स्नान, नित्य पूजा-अर्चना तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात ही मंदिर के कपाट पुन: श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। अंबुवासी महायोग के सुचारु संचालन के लिए कामाख्या मंदिर के बरदेउरी समाज, अंबुवासी महायोग संचालन समिति, कामरूप महानगर जिला प्रशासन, गुवाहाटी महानगर पुलिस, पर्यटन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों ने व्यापक तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस वर्ष भी सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक केवल पैदल ही मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। महायोग के दिनों में बीच-बीच में हुई हल्की बारिश के बावजूद देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से नीलाचल पहाड़ी क्षेत्र पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। नेपाल, भूटान के अलावा जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों से आए विदेशी श्रद्धालु भी अपने-अपने पंडाओं के आवास तथा अतिथिगृहों में ठहरकर पूजा-अर्चना में भाग ले रहे हैं। कामाख्या मंदिर के बरदेउरी समाज के बरदोलोई कविंद्र प्रसाद शर्मा, सरुदोलोई हिमाद्री शर्मा तथा सचिव ज्ञान नाथ शर्मा ने बताया कि इस वर्ष नीलाचल पहाड़ी पर बाहरी श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार के आवासीय शिविर अथवा भोजन व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि दशानामी अखाड़े में कुछ साधु-संतों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। उधर नामनि कामाख्या तथा पांडु में कोई नि:शुल्क चिकित्सा सेवा तथा अन्न सेवा की शिविर लगाए गए।

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने ईरान ने पीएम मोदी को दिया न्योता

तेहरान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिकी-इजराइली हमले में मारे गए थे। उनकी मौत 28 फरवरी को हुई थी। अब 4 चार महीने बाद उनका अंतिम संस्कार होगा, जो कि 5 से 9 जुलाई तक होगा। इसमें शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति पीएम मोदी को बुलाया है। डिप्लोमैटिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में बुलाया है। हालांकि, पीएम को बुलाए जाने के बारे में दिल्ली से कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बता दें कि अब तय की गई तारीख से पहले अली खामेनेई का अंतिम संस्कार पहले मार्च में होना था। हालांकि, इसे टाल दिया गया था क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई लंबी खिंच गई थी। अब यह कार्यक्रम तेहरान में होगा। 86 साल के खामेनेई फरवरी में अपने परिसर पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मारे गए थे। खामेनेई ने 1989 में अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान की कमान संभाली थी। खुमैनी ने ही एक दशक पहले इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की थी। जहां खुमैनी उस क्रांति के पीछे की वैचारिक ताकत थे, जिसने पहलवी राजशाही के शासन को खत्म किया, वहीं खामेनेई ने सैन्य और अर्ध-सैन्य ढांचे को आकार दिया। खबरों के मुताबिक, अयातुल्ला खामेनेई अपने आवास में रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मोहम्मद पाकपूर और सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका और इजराइल ने उनके ठिकाने पर भीषण बमबारी की थी। ये हमला इतना भीषण था कि अली खामेनेई की मौके पर ही मौत हो गई थी।

सोने की चेन छिनकर भागते समय दो चोर गिरफ्तार

बरपेटा (हिंस)। बरपेटारोड शहर की मुख्य सड़क से आम लोगों के गले से चेन छीनकर आतंक मचाने वाले दो शातिर चोरों को आखिरकार बुधवार को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सोने की चेन छीनते समय पकड़े गए दोनों चोरों की पहचान अनिकेत कुमार और रविंद्र कुमार के रूप में की गयी है। चोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बाइक (एएस-14जी-1715) भी स्थानीय लोगों ने जब्त कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि घटना के अनुसार, आज बरपेटा जिला के बरपेटा रोड के गहरी बाजार इलाके में चलते समय, अरविंद घोष उर्फ़ शंभू नामक युवक के गले की चेन छीनने की कोशिश करने के दौरान युवक ने बाइक से आए दोनों चोरों को पकड़ लिया। इस बीच लोगों ने दोनों चोरों की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों के अनुसार, बीती रात के समय दोनों चोर बबुपारा के राजपथ से सुबीर साहा नामक एक व्यक्ति की सोने की चेन छीनकर भाग निकले थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले भी इन दोनों चोरों ने एक अन्य व्यक्ति से सोने की चेन छीनी थी। वर्तमान में दोनों चोरों को बरपटा रोड एफआरयू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

ट्रेन की चपेट में आने से दो दोस्तों की मौत

बरपेटा (हिंस)। बरपेटा जिला शहर मुख्यालय के समीप ट्रेन की चपेट में आने से दो दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बरपेटा शहर के आजाद नगर के दो किशोर दोस्त की मौत ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही हो गई। मृतकों की पहचान जहांगीर आलम और मुस्तफा खान के रूप में की गई है। दोनों का शव रेलवे ट्रैक के ऊपर बरामद किया गया। रेलवे पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

अंबुबासी मेला, भारत सेवाश्रम संघ ने लगाया दो दिवसीय सेवा शिविर

गुवाहाटी (हिंस)। नीलाचल पहाड़ पर स्थित विश्व विख्यात अंबुबासी मेले में तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए भारत सेवाश्रम संघ पूरी निष्ठा के साथ आगे आया है। मेले के पावन अवसर पर संघ द्वारा नगर के पांडु केबिन इलाके में दो दिवसीय विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं के बीच सूखा भोजन (मुरमुरा, बिस्कुट), शुद्ध पेयजल और विभिन्न प्रकार के फलों का वितरण किया गया। पिछले दिन सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश भी संघ के सेवा कार्यों को रोक नहीं सकी। प्रतिकूल मौसम के बावजूद स्वयंसेवकों ने बारिश की परवाह किए बिना निरंतर अपनी सेवाएं जारी रखीं। सेवा के प्रति उनके इस समर्पण, अनुशासन और जज्बे ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। इस पूरे महायज्ञ को सफल बनाने में भारत सेवाश्रम संघ की पांडु शाखा के प्रधान स्वामी वरुणानंदजी महाराज और सुब्रत महाराज ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में संघ के उत्साही और समर्पित महिला व पुरुष स्वयंसेवकों ने दिन-रात एक कर तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद की। शिविर में आए अनगिनत श्रद्धालुओं ने भारत सेवाश्रम संघ के इस मानवीय कार्य की प्रशंसा की।

पूसीरे ने हाफलंग-न्यू हाफलंग ट्रांसमिशन लाइन किया चालू

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने 17 जून को 14:22 बजे हाफलंग ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) से न्यू हाफलंग ट्रैक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस) तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू किया। यह रेल बिजलीकरण के मिशन में एक उल्लेखनीय सफलता है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लामडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन में रेल बिजलीकरण परियोजना का एक अहम हिस्सा पूरा हो गया है। न्यू हाफलंग ट्रैक्शन सब-स्टेशन का चालू होना इस चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। यह रूट बराक वैली और पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेल लिंक है। इसके चालू होने के साथ ही, ट्रैक्शन पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी मुख्य काम अब पूरे हो गए हैं। परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और आवश्यक जांच, निरीक्षण और ट्रायल रन पूरा होने के बाद, आने वाले सप्ताह में इस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाए जाने की उम्मीद है।

पृष्ठ एक का शेष

अरुणाचल बाढ़ : पांच व्यक्ति...

नागरकोटी मेहता के अनुसार, भूस्खलन के कारण प्रभावित यजाली और होज-पोटिन, दोनों तरफ से प्रभावित हुए हैं। सडके बंद होने के करण प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल हो गया है। पोटिन और पोसा के बीच फंसा एक भू-वैज्ञानिक (जियोलॉजिस्ट) बचाव का इंतजार कर रहा है। जिला प्रशासन ने बताया कि शुरू में एक महिला के लापता होने की खबर थी, लेकिन ताजा रिपोर्टों से पता चलता है कि पांच लोगों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अधिकारियों ने अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है। बचाव कार्यों पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि निपको प्रोजेक्ट साइट पर बना हेलीपैड क्षतिग्रस्त हो गया है और सड़क संपर्क टूट गया है। जिले के अन्य अधिकारी साइट तक नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि जिला उप उपायुक्त, पुलिसकर्मियों और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की टीमें पैदल ही उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) भी कई जगहों पर सड़क जाम होने के कारण प्रभावित जगह तक नहीं पहुंच पाई है। अधिकारियों ने बताया कि पान्योर प्रोजेक्ट के प्रमुख इस मुश्किल हालात में फंसे हुए थे। निपको ने एहतियात के तौर पर अपना पावरहाउस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और बांध से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। मौसम और पहुंचने की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क साफ करने, बचाव और बहाली का काम चल रहा है।

हाई अलर्ट पर ...

के जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे कड़ी निगरानी रखें और समय रहते बचाव और राहत के उपाय करें। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसियों की टीमों को तैनात करने के लिए तैयार रखा जा रहा है। साथ ही, जमीनी स्तर के अधिकारियों को नदियों के हालात और जोखिम वाली जगहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। निचले और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन की सलाह के अनुसार सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से गुजारिश है कि वे पानी से भरे इलाकों में न जाएं और इस दौरान ब्रह्मपुत्र व अन्य नदियों में छोटी नावों या अन्य छोटे जहाजों से यात्रा करने से बचें, क्योंकि नदियों के बहाव में काफी तेजी आने की आशंका है। असम सरकार सभी संबंधित एजेंसियों और जिला प्रशासनों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है और जन-सुरक्षा के हित में जरूरत के अनुसार सलाह और अपडेट जारी करती रहेगी।

नए एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड ...

गई है, जिसे चार लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल परिवहन सुनिश्चित करना है। यह कॉरिडोर गुवाहाटी, शिलांग और सिलचर के बीच संपर्क को मजबूत करेगा और साथ ही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन कड़ी के रूप में काम करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से माल और यात्रियों की आवाजाही में काफी सुधार होगा, रसद लागत कम होगी और बाजारों तक तेजी से पहुंच संभव होगी। इस कॉरिडोर से पूर्वोत्तर के कई लोकप्रिय स्थलों तक सड़क संपर्क में सुधार होने से पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क राज्य सरकार द्वारा केंद्र के सहयोग से चलाए जा रहे व्यापक अवसंरचना परिवर्तन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य निर्बाध परिवहन गलियारे बनाना है जो आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकें। अवसंरचना विशेषज्ञों ने पाया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए बेहतर सड़क संपर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र अक्सर कठिन भूभाग और लंबे यात्रा समय के कारण रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करता है। शिलांग-सिलचर कॉरिडोर के पूरा होने के बाद, इसके पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है, जो व्यापार को सुगम बनाएगा, आवागमन को बढ़ाएगा और अंतर-राज्यीय संपर्क को मजबूत करेगा, साथ ही क्षेत्र के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देगा।

असम के स्वास्थ्य सेवा ...

जा रहे हैं। उनके द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अनुमानित 8,233 करोड़ रुपए के निवेश से 11 नए मेडिकल कॉलेज परिसरों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। इनमें से पांच परिसरों के 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है, जबकि नए संस्थानों से जुड़े छह अस्पतालों का निर्माण 80 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। पांच अन्य अस्पतालों पर काम साथ-साथ चल रहा है, और चार अतिरिक्त परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असम के प्रत्येक जिले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के अवसरों का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इस विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य की क्षमता मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि चल रही पहल से डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य पेशेवरों की एक नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे विशेष चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होगी। पिछले कुछ वर्षों में, असम चिकित्सा शिक्षा अवसंरचना के मामले में सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है। राज्य सरकार ने लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे एमबीबीएस सीटों और स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह विस्तार गुवाहाटी स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों जैसी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरक है, जिन्होंने राज्य में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। सरकार का मानना है कि ये निवेश असम भर के लोगों के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, साथ ही दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे।

असम में बड़ा प्रशासनिक ...

असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। बरपेटा जिले के आयुक्त रोहन कुमार झा को बराक घाटी विकास विभाग में सचिव और असम रेजिलिएंट रूरल ब्रिज कार्यक्रम के परियोजना निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव हिवारे निसर्ग गौतम को एआईडीसी के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें वित्त विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। कछार जिला आयुक्त आयुष गर्ग को समग्र शिक्षा एक्सोम मिशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि बंगाईगांव जिला आयुक्त दिबाकर नाथ को धुबड़ी में जिला आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है। कई जिला प्रशासनों में भी नेतृत्व परिवर्तन देखा गया। दक्षिण शालमारा-मानकाचर के जिला आयुक्त राहुल कुमार गुप्ता को कछार के जिला आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। उदालगुड़ी के जिला आयुक्त जय विकास को हैलाकांदी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि माजुली की जिला आयुक्त सृष्टि सिंह को मोरीगांव का जिला आयुक्त नियुक्त किया गया है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव परिक्षित थौदम को दक्षिण शालमारा-मानकाचर का जिला आयुक्त नियुक्त किया गया है। सहायक सचिव संजय दत्त को होजाई का जिला आयुक्त और रातुल चंद्र पाठक को माजुली का जिला आयुक्त बनाया गया है। मोरीगांव की जिला आयुक्त अनामिका तिवारी को उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है। नोबोदीप पाठक को बरपेटा का जिला आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि पुलक पाटगिरी को उदालगुड़ी का जिला आयुक्त नियुक्त किया गया है। दरंग जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कराबी सैकिया करण को विश्वनाथ का जिला आयुक्त नियुक्त किया गया है। विश्वनाथ के जिला आयुक्त लखीनंदन शहरिया को बंगाईगांव के जिला आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है, और गकुल चंद्र ब्रह्म को चिरांग के जिला आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। राज्य सचिवालय में भी फेरबदल किया गया है। पी. विजय भास्कर रेड्डी को अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि आदित्य विक्रम यादव को असम प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय में प्रशिक्षण निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसांडा मैग्डालिन पर्टिन का तबादला गृह एवं राजनीतिक विभाग से मुख्यमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर किया गया है। इन तबादलों को जनसेवा के हित में किया गया बताया जा रहा है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

तारातला में निर्माणाधीन...

कोलकाता नगर निगम की संयुक्त टीमें युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। मलबे में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द बाहर निकालने के लिए गैस कटर, क्रेन, एंबुलेंस और अन्य आधुनिक बचाव उपकरणों की मदद ली जा रही है। घटनास्थल से दबे हुए मजदूरों की आवाजें सुनाई देने की भी सूचना है। बचावकर्मी बाहर से उनके नाम पुकारकर उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बंदरगाह की जमीन पर उक्त चाय गोदाम का निर्माण किया जा रहा था। छत ढहने के समय बड़ी संख्या में मजदूर वहां कार्यरत थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने 30 से अधिक मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई है, हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी के लिए नवान्न से नियंत्रण कक्ष शुरू किया है। प्रभावित परिवारों और आम लोगों के लिए 1070, 8697981070, 033 22143526 तथा 033 22535185 नंबर जारी किए गए हैं। राज्य के नगर विकास एवं नगर मामलों के राज्य मंत्री डॉ. इंद्रनील खान घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों की जान बचाना है और सभी संबंधित एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। राकेश सिंह, मंत्री अग्निमित्रा पाल और नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं नगर मामलों विभाग को पूरे अभियान में समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है। वह स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के लिए रवाना हुए। इस बीच, मंत्री इंद्रनील खान ने निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता की सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। स्थानीय लोगों ने भी गोदाम के निर्माण में अनियमितता और अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक जांच अभी शुरू नहीं हुई है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद हादसे के कारणों और निर्माण की अनुमति संबंधी सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।

बोड़ो शांति समझौते के...

सशक्त विधायी सुरक्षा सुनिश्चित करना और बोड़ो संस्थानों की शासन शक्तियों का विस्तार करना शामिल है। आब्सू के अनुसार, बोड़ो समुदाय की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को पूरा करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इन प्रावधानों का पूर्ण और त्वरित कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। छात्र संगठन ने विशेष रूप से सीमा विस्तार और संस्थागत उन्नयन पर तत्काल प्रगति की मांग की। इसके अलावा, आब्सू ने इस बात पर जोर दिया कि आगामी मानसून संसद सत्र के दौरान संविधान (125वां संशोधन) विधेयक का पारित होना समझौते की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए अप्रतिबंधित है। समुदाय के धैर्य की कमी को देखते हुए, नेतृत्व ने कहा कि आगे और देरी करने से बोड़ो लोगों को अपनी राजनीतिक रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें एक अलग बोड़ोलैंड राज्य के लिए अपनी संवैधानिक अपील को पुनर्जीवित करना भी शामिल हो सकता है।

पासपोर्ट नागरिकता का ...

साल 10 पीओपीएसके खोले थे। इस साल 10 और खोले जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री वाले देशों की संख्या 27 है, जो 2019 में 16 थी। 47 देशों में भारतीयों के लिए *वीजा ऑन अराइवल* की सुविधा है और 66 देश भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा देते हैं। ज़्यादातर यूरोप के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट (आवाजाही से जुड़े समझौते) किए गए हैं। ये एकेडमिक्स, छात्रों, अप्रेंटिस, आम पर्यटकों और कारोबारियों की आसान आवाजाही में मदद करते हैं। साथ ही ये गैर-कानूनी प्रवासियों की आसानी से वापसी के लिए एक सिस्टम भी बनाते हैं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो यह साबित करने के लिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, इसके लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या आधार कार्ड काफी नहीं हो सकता है। कानून के अनुसार, 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई व्यक्ति तब तक अपने-आप नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय न हो। साल 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में 4 लोगों को राहत देने से इनकार कर दिया था। इन पर अवैध प्रवासी होने का आरोप था, भले ही इन्होंने यह साबित करने के लिए पासपोर्ट (जो बाद में रद्द कर दिए गए थे), आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र पेश किए थे कि वे भारतीय हैं। जस्टिस केयू चंडीवाल ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, कानून के तहत ऐसे आवेदक के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसके माता-पिता भारतीय नागरिक थे। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। कानून के तहत, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो वह नागरिकता का दावा तभी कर सकता है जब उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक हो।

पाकिस्तान की चर्चित ...

प्रदर्शन के दौरान तैनात अर्धसैनिक बल के जवान सिपाही शब्बीर बलोच की मौत हुई थी। कोर्ट ने कहा कि महरंग बलोच ने प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए उकसाया था। फैसले में यह भी कहा गया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के दावों का समर्थन करते हैं। महरंग बलोच लंबे समय से बलूचिस्तान में कथित जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस मुकदमे की आलोचना की है। उनका कहना है कि आरोपियों को जेल से वीडियो लिंक के जरिये पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कार्यवाही का बहिष्कार किया। आलोचकों का मानना है कि इस फैसले से बलूच समुदाय और राज्य के बीच भरोसा और कमजोर हो सकता है। बलोच यकजहती कमेटी के आयोजक लाला अब्दुल बलोच ने मुकदमे को *बेनाम चेहरा वाला ट्रायल* बताया और कहा कि इससे विरोध और बढ़ सकता है। बलूचिस्तान सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। प्रांत के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही शब्बीर बलोच के लिए न्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने वाले लोग वास्तव में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला साबित करता है कि हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर, महरंग बलोच के वकील इसरार जट्टक ने कहा है कि इस फैसले को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं बलूच यकजहती कमेटी ने फैसले के विरोध में पूरे प्रांत में हड़ताल का आह्वान किया है।

लोकतंत्र में पद सेवा ...

उसकी सुलभता, करुणा और उत्तरदायित्व से होती है। जो नेता जनता के प्रति सम्मानजनक और सहज उपलब्ध रहते हैं, वे स्थायी विश्वास अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक में उठाए गए विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच से मेल खाते हैं, जिसमें सार्वजनिक पद को सेवा का माध्यम माना गया है। राधाकृष्णन ने वीआईपी वाहनों पर लाल बत्ती की व्यवस्था समाप्त करने और हाल में नीट अभ्यर्थियों को यातायात प्रतिबंधों से असुविधा न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा अपने प्रस्थान में देरी किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे कदम नागरिक-केंद्रित शासन के उदाहरण हैं और यह सिद्ध करते हैं कि सार्वजनिक सत्ता का उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि हर भारतीय विशेष है, हर भारतीय वीआईपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा ही सर्वोच्च धर्म है।

एआई इंसानों से सीख ...

या महिलाओं के प्रति नफरत भरा था। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ जवाबों में तो महिलाओं को संपत्ति या चीजों (ऑब्जेक्ट्स) की तरह बताया गया। यूएन ने बताया कि अरबों लोग ईमेल लिखने, प्रेजेंटेशन बनाने, कंटेंट तैयार करने और सवालों के जवाब पाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए भेदभावपूर्ण एल्गोरिदम के जरिए असमानताएं भी बढ़ रही हैं। यह कोई तकनीकी खराबी (बग) नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई इंटरनेट से सीखता है, जिसमें दशकों से चले आ रहे स्टीरियोटाइप (रूढ़िवादी सोच), पूर्वाग्रह और भेदभाव मौजूद हैं। इसलिए जब एआई इंसानी इतिहास से सीखता है, तो वह इंसानी भेदभाव को भी अपना सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर यूएन विमेन की लीड, जयथमा विक्रमनायके ने कहा कि एआई मॉडल लोगों द्वारा और लोगों के बारे में लिखे गए दशकों पुराने टेक्स्ट से भेदभाव सीखते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि महिलायें पहले से ही बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार का सामना कर रही हैं।

पाक एयरस्पेस में ...

के एयरस्पेस में थोड़ी-सी घुसपैठ की थी। एयरलाइन ने कहा 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट एआई479 के क्रू ने अमृतसर एयरपोर्ट पर गो-अराउंड (लैंडिंग रद्द करके दोबारा चक्कर लगाने) की प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान के एयरस्पेस में थोड़ी-सी घुसपैठ की थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) ने विमान को शुरू में 13 डीएमई (डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट) पर होल्ड करने का निर्देश दिया था। हालांकि, विमान एएआर की ओर बढ़ता रहा, उसने बाएं मुड़कर इंटरनेशनल बॉर्डर (आईबी) पार कर लिया, जिससे वह कुछ देर के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस में चला गया। इस प्रक्रिया के दौरान विमान एटीसी के निर्देशों का पालन नहीं कर पाया और बॉर्डर पार कर गया। एयर इंडिया ने कहा कि इस घटना की जानकारी संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दी गई है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है।

लोस अध्यक्ष से ...

प्राप्त जानकारी शिवसेना (यूबीटी) से साझा करें। संसद भवन में अध्यक्ष बिरला से मुलाकात के बाद अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के छह सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। अनिल देसाई और उन्होंने 18 जून को को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और मामले में एक अनुरोध प्रस्तुत किया। इसमें हमने अनुरोध करते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति या सांसद व्यक्तिगत रूप से या समूह में आपके पास आकर पार्टी छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, तो आपको संविधान की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के छह सांसदों के दूसरी पार्टी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने एक पत्र भेजा। इसमें अनुरोध किया गया कि घटनाक्रम से जुड़े विषय पर कुछ निर्णय लेने से पहले कृपया शिवसेना (यूबीटी) को सुना जाए। इस संबंध में अध्यक्ष बिरला ने आज हमें समय दिया था। हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत-यूके एफटीए लागू होने से पहले असम और यूके ने सहयोग के रोडमैप पर की चर्चा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बुधवार को यहां ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग के साथ बैठक की। इस बैठक का मकसद अगले महीने लागू होने वाले भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से पहले असम और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग को मजबूत करना था। बैठक में निवेश को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने, टेक्नोलॉजी को अपनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने पर ध्यान दिया गया। मुख्य सचिव के अनुसार, यह चर्चा भारत-यूके एफटीए के संदर्भ में हुई, जो 15 जुलाई, 2026 से लागू होने वाला है। उन्होंने कहा कि असम का बदलता हुआ आर्थिक माहौल यूनाइटेड किंगडम के साथ गहरे जुड़ाव के लिए बड़े अवसर पैदा करता है। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के लिए यूके पैक्ट -समर्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) की जरूरत के आकलन

और विश्लेषण की रिपोर्ट भी पेश की। इस रिपोर्ट में ग्रिड की विश्वसनीयता को मजबूत करने, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की गति बढ़ाने और असम के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन (स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव) में मदद करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। दोनों पक्षों ने गुवाहाटी में असम-यूके इंफ्रास्ट्रक्चर राउंडटेबल की योजनाओं पर भी चर्चा की। इस प्रस्तावित प्लेटफॉर्म से सस्टेनेबल शहरीकरण, ट्रांसपोर्ट, बाढ़ से निपटने की क्षमता, जलवायु-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट डिलीवरी में पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसमें यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ संभावित जुड़ाव भी शामिल है। प्रस्तावित यूके-भारत सॉवरेन एआई पार्टनरशिप के तहत उभरते अवसरों पर भी चर्चा हुई। जिन क्षेत्रों पर बात हुई, उनमें भरोसेमंद एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉवरेन क्लाउड क्षमताएं, एडवांस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम और एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क शामिल थे, जो असम की डिजिटल बदलाव की पहलों में मदद कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक ने भारत-यूके एफटीए से मिलने वाले अवसरों को बेहतर व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और संस्थागत सहयोग के जरिए ठोस नतीजों में बदलने की साझा प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। फ्लेमिंग ने एफटीए लागू होने से पहले इस बैठक को सही समय पर हुई बैठक बताया और कहा कि चर्चा में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास, खेल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई), जलवायु और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्र शामिल थे।

गुवाहाटी में 10 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में वापस भेजे जाएंगे

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के पलटन बाजार इलाके से पुलिस ने मंगलवार देर रात 10 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान वे सही पहचान और यात्रा दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। पलटन बाजार पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इन लोगों को पहले पलटन बाजार पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में जांच-पड़ताल और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बॉर्डर पुलिस को सौंप दिया। अधिकारी ने कहा कि इन लोगों की जांच-पड़ताल पूरी हो गई है। उन्होंने माना है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। अब उन्हें वापस भेजा जाएगा। पुलिस ने उस लॉज पर भी ध्यान दिया है जहां यह ग्रुप ठहरा हुआ था। लॉज के मालिक, जिनकी पहचान हृदय डेका के तौर पर हुई है, की जांच की जा रही है क्योंकि उन्होंने जरूरी पहचान दस्तावेज लिए और उनकी जांच किए बिना ही इन लोगों को वहां ठहरने दिया था।

अंबुबासी मेला : विहिप ने लगाया मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, हजारों श्रद्धालु उठा रहे लाभ

गुवाहाटी (हिंस)। कामाख्या धाम में आयोजित वार्षिक अंबुबासी मेले के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के लिए विभिन्न प्रमुख स्थलों पर मुफ्त चिकित्सा व स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। विहिप द्वारा ये शिविर कामाख्या मंदिर, मालीपाड़ा कामाख्या मंदिर, कालीपुर राजपथ, मां कामाख्या मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार और पांडु ग्राम्य देवता मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। इस कड़ी में, विश्व हिंदू परिषद के मालीगांव प्रखंड के तत्वावधान में पांडु बड़ा बाजार स्थित ग्राम्य देवता मंदिर प्रांगण में त्रि-दिवसीय मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 23 जून से शुरू हुआ है और 25 जून तक जारी रहेगा। शिविर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मालीगांव प्रखंड विहिप के अध्यक्ष अमल चंद्र दे और सचिव उत्पल शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष स्वागत समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में मृण्मय घोष और सचिव के रूप में पुलक सेनगुप्ता व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं। यह स्वास्थ्य शिविर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मरीजों की सेवा में तत्पर रहता है। शिविर में सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के अनुभवी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस शिविर

के पहले दिन से लेकर आज मिले अंतिम सूचना तक लगभग दो हजार से अधिक श्रद्धालु स्वास्थ्य जांच करा चुके हैं। मरीजों को डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार आवश्यक दवाइयां भी मुफ्त वितरित की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के दौर को छोड़कर, मालीगांव प्रखंड विश्व हिंदू परिषद पिछले कई वर्षों से अंबुबासी मेले के दौरान नियमित रूप से इस तरह के सेवा शिविरों का आयोजन करता आ रहा है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सेवा को समर्पित विहिप के इस मानवीय प्रयास की स्थानीय निवासियों और देश-विदेश से आए तीर्थयात्रियों द्वारा काफी सराहना की जा रही है।

नलबाड़ी में 1.48 करोड़ की हेरोइन जब्त, दो गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को बताया कि असम पुलिस ने नलबाड़ी जिले में 1.48 करोड़ रुपए की संदिग्ध हेरोइन जब्त की और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि, नलबाड़ी पुलिस के जवानों ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान 16 साबुनदानी में छिपाई गई 211.5 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म *एक्स* पर पोस्ट शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खेप को स्थानीय समुदायों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। अभियान के लिए नलबाड़ी पुलिस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक और खेप को हमारे समुदायों में जहर घोलने से पहले ही रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों की कीमत अवैध बाजार में लगभग 1.48 करोड़ रुपए आंकी गई है।

कोकराझाड़ : जिला उपायुक्त ने एचपीवी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की

शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश

कोकराझाड़ (विभास)। कोकराझाड़ जिले में 14 वर्ष की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे *ह्यूमन पेपिलोमा वायरस* (एचपीवी) टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं, शिक्षक और सामुदायिक हितधारक मिलकर काम कर रहे हैं। अभियान की प्रगति की समीक्षा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, कोकराझाड़ के जिला आयुक्त (डीसी) एवं जिला कार्य बल के अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती ने एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। गूगल मीट के माध्यम से आयोजित इस बैठक में संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और संबंधित अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान, डीसी पंकज चक्रवर्ती ने जिले भर में अब तक हुए टीकाकरण के आंकड़ों का बारीकी से आकलन किया। उन्होंने सभी पात्र किशोरियों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। जिला आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षेत्रीय स्तर पर तेजी लाएं। टीकाकरण अभियान के क्रियान्वयन में फील्ड स्तर पर सखी और तेजी लाई जाए। स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक मजबूत किया जाए।

कामरूप जिले में *कृषि मैपर* पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

कामरूप अमीनगांव। जिला कृषि विभाग, कामरूप की पहल पर आज जिला आयुक्त कार्यालय के सभागार में *कृषि मैपर* विषय पर एक दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का आयोजन कृषि क्षेत्र और किसानों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समन्वय को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित *कृषि मैपर* एप्लीकेशन के उपयोग और अनुप्रयोग पर किया गया। उल्लेखनीय है कि *कृषि मैपर* कृषि भूमि और कृषि गतिविधियों के डिजिटल मानचित्रण के माध्यम से कृषि क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक राष्ट्रीय परियोजना है। इस अवसर पर आयोजित तकनीकी प्रशिक्षण में कृषि निदेशालय की कृषि मैपर विशेषज्ञ पापरी शर्मा ने विषय वस्तु प्रस्तुत की। उन्होंने बीज वितरण से लेकर फसल कटाई तक की विभिन्न कृषि गतिविधियों के साथ-साथ कृषि सामग्री, उपकरणों और मशीनरी के वितरण और उपयोग की डिजिटल निगरानी व रिपोर्ट तैयार करने में *कृषि मैपर* एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने उल्लेख किया कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा कृषि गतिविधियों की प्रभावी निगरानी संभव होगी। प्रशिक्षण में उपस्थित विशेषज्ञों

ने *कृषि मैपर* के महत्व, कार्यान्वयन पद्धति, कार्यप्रणाली और विभिन्न समस्याओं के समाधान के उपायों पर प्रकाश डाला। साथ ही, निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए। अनुष्ठान में विभागीय अधिकारियों ने क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों से सभी स्तरों के कार्यों को सही ढंग से और निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा करने का आह्वान किया। संसाधन व्यक्तियों और विभागीय विशेषज्ञों ने आवश्यक प्रक्रियाओं और तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की। *कृषि मैपर* के तहत किसान पंजीकरण प्रक्रिया पर भी एक विस्तृत चर्चा आयोजित की गई। प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि कोई भी पात्र किसान पंजीकरण से वंचित न रह जाए, इस लक्ष्य के साथ प्रक्रिया को दक्षता और सटीकता से पूरा करना होगा। पंजीकरण के बाद यदि कोई किसान छूट जाता है, तो उन्हें तुरंत चिह्नित कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया गया। कृषि विभाग ने संबंधित सभी कर्मचारियों से निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने और पारदर्शिता बनाए रखते हुए किसान पंजीकरण प्रक्रिया का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में सहायक कृषि निदेशक मुकुल बर्मन, शंकर दत्त, शैलेंद्र प्रसाद सैकिया, हितेश डेका, अनुमंडल कृषि अधिकारी ज्योति ठाकुरिया, त्रिवेणी दत्त, विभिन्न कृषि विकास अधिकारी और विभाग के कई अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कृषि अधिकारी हितेश बेजबरुआ की देखरेख में आयोजित किया गया।

बदहाल सड़कों की हकीकत जानने ई-रिक्शा पर निकले विधायक जीवेश राय

कोकराझाड़(विभास)। बिलासीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीवेश राय ने आज विकास कार्यों के प्रति एक अनोखी और संवेदनशीलता भरी पहल की। क्षेत्र के भैषपाड़ा गांव में सड़कों की जर्जर स्थिति का जायजा लेने के लिए उन्होंने किसी सरकारी वाहन के बजाए एक साधारण ई-रिक्शा का सहारा लिया। उनका यह *जमीनी दौरा* इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। भैषपाड़ा गांव की आंतरिक सड़कें लंबे समय से बदहाली की मार झेल रही हैं। गड्ढों और टूट-फूट के कारण ग्रामीणों का आवागमन दूभर हो गया था। स्थानीय लोगों की बार-बार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विधायक जीवेश राय खुद भैषपाड़ा पहुंचे। उन्होंने ई-रिक्शा में बैठकर गांव की उन तमाम तंग और जर्जर गलियों का मुआयना किया, जिनसे होकर गुजरना आम जनता के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दौरे के दौरान विधायक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। सड़क की बदहाली के कारण हो रही परेशानियों को करीब से देखने के बाद उन्होंने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि अब इस मामले में देरी नहीं होगी। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। विधायक जीवेश राय के इस सरल और जमीनी दृष्टिकोण की स्थानीय जनता ने जमकर सराहना की है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि का इस तरह सड़क पर उतरकर सीधे समस्याओं को देखना एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। लोगों को अब उम्मीद है कि विधायक के इस पहल से क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आएगी और जल्द ही उन्हें आवागमन की इस समस्या से राहत मिलेगी।

तेजपुर नराकास की बैठक में शब्द भारती की राजभाषा हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी

गुवाहाटी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के पर्यवेक्षण में 22 जून को तेजपुर विश्वविद्यालय के काउंसिल हॉल, प्रशासनिक भवन में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक के दौरान शब्द भारती (हिंदी संसाधन केंद्र) की ओर से राजभाषा हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बैठक में भारत सरकार की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजीव नायक उपस्थित रहे। नराकास तेजपुर की उक्त छमाही बैठक में तेजपुर और इसके आसपास स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में विशेष अतिथि के रूप में तेजपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संस्थापक और वर्तमान शब्द भारती (हिंदी संसाधन केंद्र) के अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत कुमार नाथ और शब्द भारती (हिंदी संसाधन केंद्र) के सचिव, शब्द व भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार-सदस्य डॉ. मोहन कोईराला भी उपस्थित रहे। तेजपुर

विश्वविद्यालय के सौजन्य में आयोजित उक्त बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। जबकि मंच पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षा, और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उप निदेशक कार्यान्वयन राजीव नायक भी उपस्थित रहे। बैठक में अगली बैठक तेजपुर स्थित किसी भी सदस्य कार्यालय में आयोजित कराने के आह्वान के अलावा, संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण में प्रश्नावली में भरे जानेवाले उत्तर एवं संबद्ध बिंदुओं, भारत सरकार की वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 पर सांगोपांग चर्चा और नराकास वेब पोर्टल पर पंजीकरण के निदेश पर चर्चा हुई। उक्त अवसर पर शब्द भारती (हिंदी संसाधन केंद्र) द्वारा पहल की गई राजभाषा हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का नराकास के प्रतिनिधि अधिकारियों ने प्रशंसा की। प्रदर्शनी में राजभाषा हिंदी और अनुवाद से संबंधित मूल्यवान पुस्तकों के अलावा शब्द भारती प्रकाशन के विचारोत्तेजक ग्रंथ भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि शब्द भारती पिछले 25 वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के संवर्धन और भाषा की तकनीकी विकास पर अनन्य रूप से कार्य कर रही है। संस्थान के जरिए पीजीडीटी का प्रशिक्षण प्राप्त कर निकले युवा देशभर में भारत सरकार की राजभाषा स्ट्रीम पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनुवाद और हिंदी की पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा, यह संस्थान प्रति वर्ष राजभाषा में कार्य करनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए *युवा अनुवादक सम्मान* और *अनुवादश्री* पुरस्कार भी प्रदान कर रहा है। नराकास बैठक का संचालन विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक डॉ. कुल प्रसाद उपाध्याय, सदस्य सचिव, तेजपुर नराकास ने किया जबकि उनका साथ दिया श्रीमती रेखारानी हाजरिका ने। अंत में सभी को दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक संपन्न हुई।

मंत्री कौशिक राय ने अंबुबाची मेले के दौरान सफाई व्यवस्था का जायजा लिया

गुवाहाटी। असम सरकार अंबुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ-सुथरा और स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करने पर खास ध्यान दे रही है। इसी प्रतिबद्धता के तहत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौशिक राय ने आज सुबह-सुबह भूतनाथ श्मशान घाट से मां कामाख्या मंदिर तक जीएमसी द्वारा की जा रही सफाई और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने इलाके में कुल मिलाकर की गई व्यवस्थाओं और पर्यावरण की स्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जीएमसी मेयर मृगेन सरनिया और जीएमसी कमिश्नर चिन्मय प्रकाश फुकन भी मौजूद थे। पवित्र अंबुबाची महायोग के मौके पर देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु गुवाहाटी में जमा हुए हैं। दूर-दूर से आने वाले तीर्थयात्री साफ और सुखद माहौल में मां कामाख्या का आशीर्वाद ले सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी नगर निगम पूरे इलाके में लगातार सफाई और स्वच्छता अभियान चला रहा है।

कोकराझाड़ में जनगणना 2027 के लिए फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू

कोकराझाड़ (विभास)। आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण (हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस) के लिए तीन दिवसीय गहन फील्ड ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कोकराझाड़ के सर्किट हाउस में किया जा रहा है। मंगलवार से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण 25 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में जनगणना कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जमीनी स्तर के अधिकारियों की तैयारी को मजबूत करना है। प्रशिक्षण में जिले भर से लगभग 34 फील्ड ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं। उन्हें कोकराझाड़ जिले में डिजिटल जनगणना गतिविधियों को सटीक, कुशल और निर्बाध रूप से संपन्न करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में उपस्थित कोकराझाड़ के जिला आयुक्त पंकज चक्रवर्ती ने प्रशिक्षुओं के साथ संवाद किया। उन्होंने जनगणना कार्यों में सटीकता, लगन और जवाबदेही के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर एकत्र किए गए जनगणना डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ही साक्ष्य-आधारित योजना, नीति निर्धारण और प्रभावी शासन की नींव है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और सटीकता के साथ करने का आग्रह किया। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी सत्रों का संचालन असम जनगणना संचालन निदेशालय की उप निदेशक प्रणति मेधी और कोकराझाड़ के सहायक आयुक्त भास्करज्य डेका द्वारा किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स के रूप में, वे प्रतिभागियों को जनगणना कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल एप्लिकेशन, डिजिटल डेटा सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रियाओं और भारत के महापंजीयक द्वारा निर्धारित मानक हाउस-लिस्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में व्यापक जानकारी दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जिले में जनगणना 2027 के सफल कार्यान्वयन के लिए तैयारियों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे सटीक और विश्वसनीय जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रह सुनिश्चित हो सके।

नगांव में महेश नवमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न, मेधावी छात्र-छात्रओं का हुआ सम्मान

नगांव (विभास)। माहेश्वरी वंशोत्पति दिवस के उपलक्ष्य मे आयोजित महेश नवमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ समग्र देश के साथ नगांव मे भी शनि मंदिर रोड स्थित श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति भवन मे मनाया गया। एक दिवसीय महेश नवमी उत्सव के दौरान सर्वप्रथम भगवान महेश का दरबार सजाया गया और पंडित सचिन शर्मा के सानिध्य मे पूजा अर्चना के साथ सभी ने बाबा भोलेनाथ की आराधना और आरती की। इस वक्त आयोजन स्थल भगवान महेश के जयकारो से गुंज उठा। मुख्य यजमान रहे सभा के निवर्तमान सचिव महावीर प्रसाद झंवर ने सपत्नीक पूजा विधि संपन्न करवाई। भजन कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश वंदना से श्याम झंवर ने किया। तत्पश्चात माहेश्वरी महिला समिति की सदस्याओ मे से संतोष दरक, कुसुम झंवर, यशोदा धूत, शर्मिला माहेश्वरी, माया राठी व हेमा झंवर ने बधाई गीत प्रस्तुत किया। साथ ही माहेश्वरी युवा संगठन, नगांव की सचिव पूजा माहेश्वरी, अन्नु तोषनीवाल, भाविका झंवर, मुस्कान गगड़, मनषी तोषनीवाल ने महेश वंदना पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम मे चार चांद लगा दिए। तत्पश्चात कार्यक्रम मे शहर की नामचीन गायिका गुणगुन बोरा ने भी भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। बाद मे मेधावी छात्र छात्राओ मे से सीए वरूण कर्वा, विधि धूत, मनन सोनी, अरमान धूत, भाविका झंवर, नैना पेड़ीवाल, आयुष माहेश्वरी, रोनक माहेश्वरी (होजाई), उमंग माहेश्वरी (होजाई), हर्ष माहेश्वरी (होजाई) व मुकेश पेड़ीवाल, को शैक्षणिक योग्यता के लिए फुलाम गोमछा, प्रस्शती पत्र व पेन प्रदान कर सम्मानित किया गया। बुजुर्ग महिला सम्मान श्रीमती शाकुंतला देवी कवा (धर्मपत्नी-स्व. श्याम सुंदर कर्वा) और श्रीमती सरोज देवी मुंदड़ा (धर्मपत्नी-स्व. शिवरतन मुंदड़ा)

को प्रदान दिया गया। जिसमे साल, फुलाम गोमछा व प्रशस्तिपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समाप्ती से पूर्व पूजा माहेश्वरी के निर्देशन व कोरियोग्राफी मे नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुती वर्षा सेठिया माहेश्वरी, पूजा तोषनीवाल चांडक, श्रुति मालानी, रुची पेड़ीवाल, सोनम बागड़ी, कल्पना धूत, स्नेहा गगड़, सोनाली काबरा, सारिका झंवर सुमन माहेश्वरी ने प्रस्तुत की। जिसके लिए सभी नृत्यांगनाओ व कलाकारो की खूब सराहना हुई। उक्त नृत्य नाटिका मे नव दुर्गा के नौ स्वरूप का वर्णन और आज की नारी की दुर्गा शक्ति का बखान किया गया। आज की नारी विषय पर आधारित नृत्य को पूजा माहेश्वरी, मुस्कान गगड़, अन्नु तोषनीवाल, भाविका झंवर व मानषी तोषनीवाल ने प्रस्तुत किया। जो केवल नौ रूप ही नहीं बल्कि नारी शक्ति के नौ आयाम भी है को दर्शाया गया। शक्ति जो सृजन भी करती है, संरक्षण भी करती है और आवश्यकतानुसार संहार भी करती है। इस नृत्य नाटिका की लोगो ने खुब सराहना की। शक्ति आधारित नृत्य नाटिका मे नोएडा के पत्रकार रोहित सिंह ने अपनी आवज देकर उपस्थित लोगो का मनमोह लिया। इससे पहले बच्चो ने भी शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया जिसमे किसा गगड़, तनिष्क झंवर, गौरांश झंवर, खनक माहेश्वरी, यूविका झंवर, रिधान बागड़ी, प्रयांश धूत, यूविका झंवर, तनवी कर्वा, रीत झंवर, रौनक बिहानी, कृषिका गगड़ व यथार्थ कर्वा शामिल थे। अरमान धूत व मयंक बिहानी ने भी भोलेनाथ के भजन पर खुबसूरत नृत्य की प्रस्तुती दी। कार्यक्रम का संचालन सभा के पूर्व सचिव अजित माहेश्वरी ने किया। कार्यक्रम संपन्न होने से पूर्व नृत्य नाटिका के निर्देशन व कोरियोग्राफी के लिए पूजा माहेश्वरी और अन्य सभी कलाकारो को गिफ्ट, प्रशस्तिपत्र व फुलाम गोमछा प्रदान कर अभिनंदन किया गया।

संपादकीय

रद्द करो दलबदल कानून

आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) के सांसद दलबदल कर चुके हैं। 'आप' के 7 सांसद राज्यसभा के थे, लेकिन अभी लोकसभा के 3 सांसदों की बोली तय नहीं हुई है। तृणमूल और उद्धव शिवसेना के 26 लोकसभा सांसद तोड़े जा चुके हैं। यानी बिक चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता पार्टी को इतना मासूम और तटस्थ करार देने का ढोंग न करें, क्योंकि सांसद उसके अघोषित 'ऑपरेशन दो-तिहाई' के मद्देनजर तोड़े जा रहे हैं। नहीं तो बागियों की बैठकों में भाजपाई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री क्या करते रहे हैं? हररोज, हर पल चाय-पानी ही चलता रहता है क्या? बहरहाल शिवसेना (उद्धव) के 'बिकाऊ सांसद' महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलीन हो चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह अब उसे ही 'असली शिवसेना' मानते हैं। वह काफी हद तक उचित भी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे ही 'असली शिवसेना' की मान्यता दी है और चुनाव चिह्न भी उसे ही सौंप दिया गया है। चुनाव आयोग सक्षम, अधिकार प्राप्त संवैधानिक संस्था है। इसी तरह शरद पवार ने जिस एनसीपी की स्थापना की थी, अब वह उनके सगे भतीजे अजित पवार (अब दिवंगत) के कब्जे में है। उसे ही 'असली एनसीपी' की मान्यता प्राप्त है। चुनाव चिह्न भी उसे ही आवंटित किया जा चुका है। हालांकि ये दोनों मामले अभी सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन हैं। तृणमूल कांग्रेस में तो बागी 60-65 विधायकों ने सामूहिक निर्णय लेकर ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अरूप राय को नया अध्यक्ष चुन लिया है। कुछ उपाध्यक्ष और महासचिव भी तय किए गए हैं। कार्यकारिणी नई बनाना भी तय लगता है। उसके बाद चुनाव आयोग की दहलीज पर दस्तक दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह का 'आशीर्वाद' है, तो आयोग उसे भी 'असली तृणमूल' घोषित कर देगा। गृहमंत्री का संकल्प है कि ममता की तृणमूल का 'सर्वनाश' किए बिना वह राहत की सांस महसूस नहीं करेंगे। तृणमूल के बागी 20 लोकसभा सांसद तो 'नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया' सरीखी गुमनाम और बिन विधायक-सांसद की बौनी पार्टी में विलय कर चुके हैं। फिलहाल उनका प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला के विचाराधीन है। भाजपा तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी द्रमुक पर भी डोरे डाल रही है, क्योंकि लोकसभा में उसके 22 सांसद हैं। बेशक राज्य में उनकी सरकार पराजित हो चुकी है। अभी तो छोटे और 1-2 सांसद वाले दलों को 'खरीदना' शेष है। ये तमाम दलबदल भीतरी असंतोष और नेतृत्व के प्रति बगावत के ही निष्कर्ष नहीं हैं, बल्कि सांसद तोड़े जा रहे हैं। 52वां और 91वां संविधान संशोधन कर जो दलबदल विरोधी कानून बनाया गया था, उसमें एक-तिहाई अथवा दो-तिहाई सांसदों-विधायकों के पालाबदल की व्यवस्था रही है। अब यह कानून कागजी साबित हो रहा है, क्योंकि जन-प्रतिनिधि बेचे-खरीदे जा रहे हैं। तो फिर इस कानून की जरूरत क्यों है? जैसा 1985 और 2003 से पहले था, वैसा ही रहने दीजिए। सांसदों-विधायकों को दलबदल करने की कानूनन छूट दे दी जाए। अरे, खुला बाजार सजा है, बोलियां लगने दीजिए। लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता की परवाह क्यों की जाए? अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका सरीखे बड़े लोकतांत्रिक देशों में दलबदल निरोधक कानून नहीं है। फिर भी वहां इतना दलबदल नहीं होता, जिस व्यापक स्तर पर भारत में होता रहा है। उनके लिए, राजनीतिक, चुनावी अनुशासन बेहद मायने रखता है। इस संदर्भ में, एक देशवासी होने के नाते, हमारा सुझाव है कि दलबदल कानून को रद्द कर दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यह सुझाव नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें दलबदल कराने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की आड़ चाहिए। वैसे भी देश में दलबदल की परंपरा पुरानी है और आजादी के पहले और उसके तुरंत बाद राजनीतिक दल टूट कर बिखरते और नए दल बनाए जाते रहे हैं। कांग्रेस 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी टूट कर आचार्य कृपलानी ने 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी' बनाई। और भी कई उदाहरण हैं। अब पहले से भी ज्यादा दलबदल होने लगा है।

तृणमूल और उद्धव शिवसेना के 26 लोकसभा सांसद तोड़े जा चुके हैं। यानी बिक चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता पार्टी को इतना मासूम और तटस्थ करार देने का ढोंग न करें, क्योंकि सांसद उसके अघोषित 'ऑपरेशन दो-तिहाई' के मद्देनजर तोड़े जा रहे हैं। नहीं तो बागियों की बैठकों में भाजपाई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री क्या करते रहे हैं? हररोज, हर पल चाय-पानी ही चलता रहता है क्या? बहरहाल शिवसेना (उद्धव) के 'बिकाऊ सांसद' महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलीन हो चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह अब उसे ही 'असली शिवसेना' मानते हैं। वह काफी हद तक उचित भी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे ही 'असली शिवसेना' की मान्यता दी है और चुनाव चिह्न भी उसे ही सौंप दिया गया है। चुनाव आयोग सक्षम, अधिकार प्राप्त संवैधानिक संस्था है। इसी तरह शरद पवार ने जिस एनसीपी की स्थापना की थी, अब वह उनके सगे भतीजे अजित पवार (अब दिवंगत) के कब्जे में है। उसे ही 'असली एनसीपी' की मान्यता प्राप्त है। चुनाव चिह्न भी उसे ही आवंटित किया जा चुका है। हालांकि ये दोनों मामले अभी सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन हैं।

कुछ अलग

फालोअर के मारे आभासी संत बेचारे

बड़े दिनों बाद कल मैं उनके लाइव दर्शन करने गया। फेसबुक पर तो उनके दर्शन किसी न किसी पोस्ट को लेकर दिन में दस दस बार होते ही रहते हैं। उस वक्त वे सिर में हाथ दिए मौन बैठे थे तो मुझे उनकी चिंता हुई। कहीं आभासी जगत में विचरण करते करते अस्वस्थ तो नहीं हो गए? सो उनसे हमदर्दी जताते पूछ बैठा, 'मित्र! क्या हो गया? आभासी दुनिया में भजन करते करते सिर में दर्द हो रहा है क्या? सिर दर्द की गोली दूं?' 'नहीं। मेरे सिर दर्द नहीं हो रहा', उन्होंने कहा और वैसे ही सिर में हाथ दिए रहे तो मैंने फिर उनकी सहायता करने के गैर इरादतन इरादे से पुनः पूछा, 'तो पेट में दर्द हो रहा होगा?' लेकिन अबके भी मेरे पूछने पर वे पहले की तरह ही बोले, 'नहीं', लेकिन मुझे उनकी हरकतों से लगा कि उनके कहीं न कहीं, कोई न कोई दर्द है तो जरूर, पर जैसे वे मुझसे अपना दर्द कहीं छुपा रहे हों। फिर मैंने उनके माथे पर हाथ रख यह जानने की कोशिश की कि कहीं बंधु को बुखार तो नहीं हो रहा होगा! जैसे ही मैंने अपने माथे पर उनकी बॉडी का टेंपरेचर जानने की कोशिश की तो उनका टेंपरेचर बढ़ गया, 'ये क्या कर रहे हो?' 'तुम्हारा टेंपरेचर चेक कर रहा हूं। तुम तो कुछ बोल नहीं रहे हो। पर मुझे पक्का लग रहा है कि तुम्हें कुछ न कुछ जरूर हुआ है।' 'करूंगा क्या! तुम्हारी सहायता करूंगा, और क्या करूंगा! मुझसे एक बार अपना दर्द कहो तो सही। माना, तुम मेरे जीव जगत के नहीं हो। फिर भी मेरे दोस्त तो हो। दुनियाएं बदल जाने से दोस्ती नहीं बदला करती दोस्त!' मैंने इतना भर झूठी हमदर्दी से कहा कि वे मेरे कंधे पर अपना सिर रख फूट फूट कर वैसे ही रोने लगे जैसे प्रेम के दिनों में मुझसे अच्छा मिलते ही उससे अपना अपना विवाह तय कर मेरी प्रेमिकाएं प्रेम का ढोंग करती मेरे कंधे पर अपना सिर कर फूट फूट कर रोने के बाद वहां विवाह कर लेती थीं।

विभिन्न सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार देश में बड़ी संख्या में दैनिक यात्राएँ पूरी या आंशिक रूप से पैदल ही की

शहर किसके लिए: वाहन या नागरिक ?

भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। महानगरों से लेकर मध्यम और छोटे शहरों तक शहरीकरण की गति अभूतपूर्व है। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लाखों लोग प्रतिवर्ष शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। किंतु इस तीव्र शहरी विस्तार के बीच एक बुनियादी प्रश्न अक्सर उपेक्षित रह जाता है—क्या हमारे शहर अपने नागरिकों के लिए चलने योग्य (Walkable) हैं? क्या सड़कें केवल वाहनों के लिए हैं या मनुष्यों के लिए भी? हाल ही में न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार से जोड़ते हुए मौलिक अधिकार की संज्ञा दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गई हैं। यह एक स्वागत योग्य संवैधानिक प्रोत्साहन है, क्योंकि यह पहली बार शहरी अवसंरचना को केवल निर्माण और यातायात के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और मानव गरिमा के संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या केवल न्यायिक घोषणा या कानूनी मान्यता से भारतीय शहर वास्तव में पैदल यात्रियों के अनुकूल बन जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। वास्तविक परिवर्तन तब आएगा जब शहरी नियोजन की सोच वाहन-केंद्रित मॉडल से हटकर मानव-केंद्रित मॉडल की ओर अग्रसर होगी और समाज में पैदल चलने को सम्मानजनक एवं प्राथमिक परिवहन माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। भारत में पैदल चलना कोई सीमित गतिविधि नहीं है। विभिन्न सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार देश में बड़ी संख्या में दैनिक यात्राएँ पूरी या आंशिक रूप से पैदल ही की जाती हैं। गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएँ, बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिक सबसे अधिक पैदल यात्रा करते हैं। इसके बावजूद शहरी नियोजन में पैदल यात्रियों को सबसे कम प्राथमिकता मिलती है। अधिकांश शहरों में फुटपाथ या तो हैं ही नहीं, या इतने संकरे, टूटे हुए और अतिक्रमण से घिरे होते हैं कि उनका उपयोग करना कठिन हो जाता है। कई स्थानों पर फुटपाथ पार्किंग स्थल, दुकानों के विस्तार, ठेलों या निर्माण सामग्री के भंडारण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस स्थिति का सबसे दुखद परिणाम सड़क दुर्घटनाओं में दिखाई देता है। भारत विश्व में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में अग्रणी देशों में है। इन दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या पैदल यात्रियों की होती है। सड़क पार करने, फुटपाथों की अनुपलब्धता और वाहनों की तेज गति के कारण हजारों लोग प्रतिवर्ष अपनी जान गंवाते हैं। यह केवल परिवहन का संकट नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। समय के साथ न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या का दायरा बढ़ाते हुए स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे अधिकारों को भी इसमें शामिल किया है। सुरक्षित पैदल मार्गों का

महानगरों से लेकर मध्यम और छोटे शहरों तक शहरीकरण की गति अभूतपूर्व है। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लाखों लोग प्रतिवर्ष शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। किंतु इस तीव्र शहरी विस्तार के बीच एक बुनियादी प्रश्न अक्सर उपेक्षित रह जाता है—क्या हमारे शहर अपने नागरिकों के लिए चलने योग्य (Walkable) हैं? क्या सड़कें केवल वाहनों के लिए हैं या मनुष्यों के लिए भी? हाल ही में न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार से जोड़ते हुए मौलिक अधिकार की संज्ञा दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गई हैं।

अधिकार इसी प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टिकोण का विस्तार है। जब कोई नागरिक अपने घर से विद्यालय, कार्यालय, अस्पताल या बाजार तक सुरक्षित रूप से नहीं पहुँच सकता, तब उसके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अधूरा रह जाता है। इसलिए फुटपाथ केवल सीमेंट और कंक्रीट की संरचना नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक हैं। फिर भी केवल अधिकार की घोषणा पर्याप्त नहीं है। भारत में अनेक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त होने के बावजूद उनके क्रियान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और भोजन का अधिकार इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार फुटपाथ के अधिकार को भी व्यवहार में उतारने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति, वित्तीय निवेश और संस्थागत सुधार आवश्यक होंगे। भारतीय शहरी शासन की सबसे बड़ी समस्या इसका वाहन-केंद्रित दृष्टिकोण है। स्वतंत्रता के बाद विकास का जो मॉडल अपनाया गया, उसमें चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवरों और एक्सप्रेसवे को आधुनिकता का प्रतीक माना गया। शहरों की सफलता को वाहनों की गति और सड़क क्षमता के आधार पर मापा गया। परिणामस्वरूप पैदल यात्री, साइकिल चालक और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ता हाशिए पर चले गए। नगर नियोजन का उद्देश्य लोगों की सुविधा के बजाय वाहनों की निर्बाध आवाजाही बन गया। यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत है। भारत में निजी कारों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जबकि अधिकांश नागरिक सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल यात्रा पर निर्भर हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक धन का बड़ा हिस्सा उन परियोजनाओं पर खर्च होता है जो मुख्यतः वाहन मालिकों को लाभ पहुँचाती हैं। इससे संसाधनों के वितरण में असमानता बढ़ती है और गरीब वर्गों की गतिशीलता प्रभावित होती है। फुटपाथों की स्थिति लैंगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महिलाएँ, विशेषकर कामकाजी महिलाएँ और छात्राएँ, सुरक्षित और प्रकाशयुक्त पैदल मार्गों पर अधिक निर्भर रहती हैं। खराब फुटपाथ, अपर्याप्त रोशनी और असुरक्षित सार्वजनिक स्थान उनके आवागमन को सीमित करते हैं। इसी प्रकार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए बाधा-रहित फुटपाथ जीवन की आवश्यक शर्त हैं। यदि शहरी अवसंरचना इन समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती, तो शहर समावेशी नहीं कहे जा सकते। मानव-केंद्रित शहरी नियोजन का विचार इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसका मूल सिद्धांत है कि शहरों को वाहनों के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। सड़कें केवल यातायात गलियारे नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक स्थान भी हैं। फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन और सार्वभौमिक पहुँच (Universal Accessibility) इस मॉडल के प्रमुख तत्व हैं। विश्व के अनेक शहरों ने इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई शहरों ने पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी, वायु प्रदूषण में नियंत्रण और नागरिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हासिल किया है। इन अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षित और चलने योग्य शहर केवल यातायात प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि समग्र शहरी विकास की रणनीति हैं। भारत में भी कुछ सकारात्मक पहलें देखने को मिली हैं। कुछ शहरों ने 'कम्प्लीट स्ट्रीट्स' की अवधारणा को अपनाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत सड़कों को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित बनाया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी कई स्थानों पर फुटपाथों के विकास और सार्वजनिक स्थलों के पुनरोद्धार के प्रयास हुए हैं। किंतु इन पहलों का प्रभाव अभी सीमित है और वे व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन का रूप नहीं ले सकी हैं। इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। पहला, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता सीमित है। अधिकांश नगर निकाय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। सड़क निर्माण, यातायात प्रबंधन, जल निकासी, बिजली और दूरसंचार से जुड़ी एजेंसियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं, जिसके कारण फुटपाथ बार-बार खोदे जाते हैं और उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरा, नागरिक सहभागिता का अभाव है। योजनाएँ अक्सर ऊपर से नीचे (Top-down) दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। फुटपाथों के अधिकार की सफलता के लिए केवल कानूनी उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय किसी अधिकार की घोषणा कर सकते हैं और सरकारों को निर्देश दे सकते हैं, लेकिन शहरों के चरित्र को बदलने के लिए सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन सबसे पहले नीति-निर्माण में दिखाई देना चाहिए। शहरी परिवहन नीतियों में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक सड़क परियोजना में फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। दूसरा, बजट आवंटन में परिवर्तन आवश्यक है।

देश दुनीया से

जड़ें और विस्थापन, आधुनिक विचारचर्या का द्वंद्व

मानव के जीवन का संघर्ष बाहर से होकर अंदर यानी मन के भीतर तक पहुंच चुका है। एक स्थान पर जीवनचर्या से बंधे रहकर जो असंख्य अनुभव होते हैं, वे तब अपनी प्रभावन क्षमता खो देते हैं, जब कुछ कम या अधिक दिनों के लिए अन्य स्थान पर जाना, ठहरना अथवा रहना होता है। एक रचनात्मक व्यक्ति को यह असंतुलन अच्छा नहीं लगता। इस स्थिति में वह या तो पूर्ण असंवेदनशील हो उठता है अथवा संवेदनशील होने के तुच्छ प्रदर्शन में व्यस्त होता है। इन दिनों ऐसी स्थितियां बहुत अधिक दिखाई देती हैं। ग्रीष्म पर्यटनावधि में ऐसा अधिक होता है। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन कर महानगरों एवं नगरों में बसे लोग जब गर्मियों की छुट्टियों में अपने पहाड़ी गांव लौटते हैं, तो अधिसंख्य ऐसे लोग इसी अनुभव से गुजरते हैं। यह अवस्था व्यक्ति में व्यक्ति के लिए एक वैचारिक, भावनात्मक, मानसिक तथा कायिक उथल-पुथल मचाए रखती है। व्यक्ति लाख चाहकर भी वैसे एकांत, स्वभाव, दिनचर्या तथा विचारचर्या के साथ नहीं जुड़ा रह पाता, जैसा वह अपने स्थायी निवास स्थान के एकांत, स्वभाव, दिनचर्या तथा विचारचर्या से जुड़ा होता है। यही परिस्थिति एकांतिक, स्वाभाविक, दैनचार्यिक तथा वैचारिक संघर्ष उत्पन्न करती है। इस संबंध में निष्कर्ष ये निकला है कि ऐसे वातावरण से सुरक्षित रहने के लिए मस्तिष्कीय शांति व संतुलन परमावश्यक है। भौगोलिक विस्थापन केवल भौतिक धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि यह चेतना के स्तर पर एक गहरी उथल-पुथल की शुरुआत है। समकालीन युग में जब तीव्र गति से ग्रामीण अंचलों, विशेषकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से जनमानस का पलायन महानगरीय कोलाहल की ओर हुआ है, तब इस आंतरिक संघर्ष की तीव्रता कई गुना बढ़ गई है। मनुष्य आर्थिक समृद्धि और आधुनिक सुख-सुविधाओं की खोज में अपनी मूल माटी को छोडकर कंक्रीट के जंगलों में जा तो बसता है, परंतु उसका अवचेतन मन सदैव अपनी जड़ों की गंध को सहेजकर रखता है। यह गंध ही उसे हर वर्ष ग्रीष्मकाल के आगमन पर

अपने पैतृक गांवों की ओर लौटने के लिए विवश करती है। किंतु, विडंबना यह है कि यह पुनरागमन उसे वह चिर-परिचित मानसिक संतोष नहीं दे पाता, जिसकी खोज में वह यात्रा पर निकलता है। इसके विपरीत, वह एक ऐसे छिन्न-भिन्न अस्तित्व का सामना करता है जो न तो पूरी तरह शहरी हो पाया है और न ही अपनी पुरातन ग्रामीण सादगी को सुरक्षित रख सका है। इस मानसिक द्वंद्व की जड़ें उस दैनिक चक्र में निहित हैं, जिसे हम जीवनचर्या कहते हैं। महानगर की एक निश्चित, यांत्रिक और समयबद्ध दिनचर्या होती है। वहां का एकांत भी कृत्रिम होता है, जो चार दीवारों के भीतर सिमटा रहता है। जब वही व्यक्ति कुछ सप्ताह के लिए अपने शांत पहाड़ी गांव में कदम रखता है, तो वहां का असीम प्राकृतिक एकांत और अनियत समय चक्र उसकी स्थापित मानसिक व्यवस्था को झकझोर देता है। वह पाता है कि पहाड़ों की नीरवता, जो कभी उसकी आत्मा का संगीत हुआ करती थी, अब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है। यह बेचैनी विचारचर्या के स्तर पर उत्पन्न होने वाले उस असंतुलन का परिणाम है, जहां व्यक्ति अपने वर्तमान महानगरीय विचारों को अपने अतीत के परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाने में असमर्थ पाता है। वह इस अनपेक्षित बदलाव से बचने के लिए या तो पूरी तरह से उदासीन होकर स्वयं को एक बंद कमरे में कैद कर लेता है, या फिर सोशल मीडिया और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से अपनी छद्म संवेदनशीलता का भौंडा प्रदर्शन करने लगता है, जो केवल उसके आंतरिक खालीपन को ही उजागर करता है। यह उथल-पुथल केवल मानसिक धरातल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव मनुष्य की काया अर्थात उसके भौतिक शरीर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहाड़ों की शुद्ध वायु, शीतल जल और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, जो कभी उसके स्वास्थ्य का आधार थीं, अब उसके शहरीकृत शरीर के लिए एक चुनौती बन जाती हैं। खानपान का बदलाव और महानगरीय सुख-सुविधाओं की अनुपलब्धता उसके भीतर एक कायिक असंतुलन पैदा करती है। शरीर का यह तनाव सीधे तौर पर उसके भावनात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। वह अपने ही सगे-संबंधियों और ग्रामीणों के बीच स्वयं को एक अजनबी, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में महसूस करने लगता है। ग्रामीण समाज की सहज अपेक्षाएं और इस लौटे हुए व्यक्ति की महानगरीय औपचारिकता के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। यह परिस्थिति अंततः एक ऐसे त्रिआयामी संघर्ष को जन्म देती है, जिसमें व्यक्ति का स्वभाव, उसकी दिनचर्या और उसकी वैचारिक दिशा तीनों एक साथ बिखरने लगते हैं। विचारणीय पहलू यह भी है कि इस बिखराव का प्रभाव केवल उस व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, जो इस यात्रा पर है। यह उसके परिवेश, उसके परिवार और उस संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है जिसे वह पीछे छोड़ आया था और जिसके पास वह पुनः लौटकर आया है। पहाड़ी क्षेत्रों की सामाजिक संरचना अत्यंत घनिष्ठ और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। वहां प्रत्येक व्यक्ति का सुख-दुख पूरे समुदाय का साझा विषय होता है। इसके विपरीत, महानगरीय संस्कृति व्यक्तिवाद और निजता की कट्टर समर्थक है।

आप का नजरीया

पुलिस ट्रांसफर से कहीं आगे

कांगड़ा राजस्व जिला के तमाम पुलिस जिलों में एसपी बदल कर हिमाचल सरकार पुनः हवन कुंड को हवा दे रही है। इसके अलावा बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक भी ट्रांसफर के सफर पर भेज दिए गए हैं। यह सरकार की नीति और नीयत पर निर्भर करता है कि कब किस अधिकारी के पंख खोले या समेट दे, लेकिन कांगड़ा के संदर्भ में ये ट्रांसफर आर्डर एक व्यापक संदेश दे रहे हैं। खास तौर पर कांगड़ा के मुख्यालय की तैनाती पर अशोक रत्न को बदल कर जिस तरह मुख्यालय में बैठाया है, यह कोई पारितोषिक नहीं। उनके स्थान पर हिमाचल कैडर के एचपीएस अधिकारी कुलभूषण वर्मा आ रहे हैं। बिलासपुर में रहे एसपी संदीप धवल अब देहरा के पथ पर हैं, जबकि शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आइंदा बिलासपुर के पुलिस बंदोबस्त का नए सिरे से अभिषेक करेंगे। इल्मा अफरोज को कांगड़ा के सीमांत क्षेत्र की तैनाती देकर सरकार ने बहुत कुछ रेखांकित किया है। इसके अलावा भी कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने दायित्व की नई कमान थाम रहे हैं। चुनाव के ठीक डेढ़ वर्ष पूर्व सत्ता को अपनी छवि, जनता को अपनी मिलकीयत और विभाग को अपनी पृष्ठभूमि सजाने का अवसर मिल रहा है। पुलिस व्यवस्था के अपने प्रयोग और इस लिहाज से सुक्खू सरकार ने कानून व्यवस्था के नए तराजू पर फेरबदल शुरू किए हैं। ट्रांसफरों का वर्तमान सिलसिला अपेक्षित तो है ही, साथ में गुणात्मक परिवर्तन की उम्मीद भी रखता है। प्रदेश की पुलिस व्यवस्था के लाजिमी पहर, इस समय पर्यटक सीजन के बिखरने की खबर दे रहे हैं। ट्रैफिक जाम के सिलसिले अगर सरकार की मौजूदगी में महसूस हों, तो बदलाव अपरिहार्य है। अटल टनल, मनाली, मकलोडगंज, शिमला, डलहौजी, कसौली, नेरचौक, कुल्लू, बैजनाथ, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, मटौर चौक व तमाम धार्मिक स्थलों जैसे अनेक स्थल हैं जहां ट्रैफिक नियंत्रण के लिए केवल एसपी नहीं, जमीन पर सिपाही चाहिए। बहुत सारे कांस्टेबल ऑन ड्यूटी चाहिए वरना सैलानियों के कटु अनुभव हिमाचल की छवि बिगाड़ रहे हैं। रोजाना सोशल मीडिया हिमाचल बनाम कई राज्य हो रहे हैं, तो यह गलत पैरवी है। प्रदेश की शांति अगर गलत पार्किंग, परिवहन संचालन और बिगड़े बोल से हो रही है, तो इसकी प्रतिक्रिया में हम पंजाब सीमा पर अवैध वसूली तथा हो-हल्ले में देख सकते हैं। हम बार-बार कहते आए हैं कि अब हिमाचल में पुलिस व्यवस्था एक ही यूनिफार्म के तहत सारा जिम्मा नहीं संभाल सकती। अपराध अब मानवीय प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान के साथ इतना बदल गया है कि इसके अपने संसाधन व तरीके हैं। हमें अलग से पर्यटक पुलिस का बंदोबस्त हर पर्यटन डेस्टिनेशन पर करना होगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस की वर्दी हर चौक-चौराहे से सडक पर रात-दिन पेट्रोलिंग तक होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ महत्त्वपूर्ण नगर निगम क्षेत्रों या जिला मुख्यालयों में पुलिस आयुक्तालयों की स्थापना करते हुए शहरी एवं ग्रामीण पुलिस के तहत कार्य वितरण होना चाहिए। कांगड़ा में तीन पुलिस जिला बनाना नाकाफी साबित हो रहा है तो इसलिए कि एक और पालमपुर में पुलिस जिला बनाने के अलावा, धर्मशाला में पुलिस कमीशनरेट बैठाना चाहिए। इसके अलावा फोरलेन मार्गों पर अगले दस सालों में यातायात वृद्धि दर को देखते हुए हाईवे पुलिस के आधार पर व्यापक व्यवस्था करनी होगी। शिमला में पुलिस मुख्यालय तो हो सकता है, लेकिन पुलिस की हर जिम्मेदारी का वितरण शिमला से नहीं हो सकता, अतः पुलिस मुख्यालय से जुड़े कई विंग या शाखाएं अब कहीं अन्यत्र शिफ्ट करनी पड़ेंगी। औद्योगिक अशांति की दृष्टि से बीबीएन में सीमांत क्षेत्रों की निगरानी का मुख्यालय, तो हमीरपुर की केंद्रीय स्थिति में ट्रैफिक नियंत्रण मुख्यालय स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह अनुसंधान, अध्ययन व ट्रेनिंग से जुड़े दायित्व का मुख्यालय डरोह में स्थापित कर देना चाहिए।

बिलासपुर में रहे एसपी संदीप धवल अब देहरा के पथ पर हैं, जबकि शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आइंदा बिलासपुर के पुलिस बंदोबस्त का नए सिरे से अभिषेक करेंगे। इल्मा अफरोज को कांगड़ा के सीमांत क्षेत्र की तैनाती देकर सरकार ने बहुत कुछ रेखांकित किया है। इसके अलावा भी कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने दायित्व की नई कमान थाम रहे हैं। चुनाव के ठीक डेढ़ वर्ष पूर्व सत्ता को अपनी छवि, जनता को अपनी मिलकीयत और विभाग को अपनी पृष्ठभूमि सजाने का अवसर मिल रहा है। पुलिस व्यवस्था के अपने प्रयोग और इस लिहाज से सुक्खू सरकार ने कानून व्यवस्था के नए तराजू पर फेरबदल शुरू किए हैं। ट्रांसफरों का वर्तमान सिलसिला अपेक्षित तो है ही, साथ में गुणात्मक परिवर्तन की उम्मीद भी रखता है। प्रदेश की पुलिस व्यवस्था के लाजिमी पहर, इस समय पर्यटक सीजन के बिखरने की खबर दे रहे हैं। ट्रैफिक जाम के सिलसिले अगर सरकार की मौजूदगी में महसूस हों, तो बदलाव अपरिहार्य है। अटल टनल, मनाली, मकलोडगंज, शिमला, डलहौजी, कसौली, नेरचौक, कुल्लू, बैजनाथ, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, मटौर चौक व तमाम धार्मिक स्थलों जैसे अनेक स्थल हैं जहां ट्रैफिक नियंत्रण के लिए केवल एसपी नहीं, जमीन पर सिपाही चाहिए।

दृष्टि कोण

जनगणना के आंकड़ों में छिपा भारत का भविष्य

वर्ष 2027 में देशभर में जनगणना का कार्य आरंभ होने जा रहा है। सामान्यतः जनगणना को देश में रहने वाले लोगों की संख्या गिनने की प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह केवल लोगों की गिनती भर नहीं है। जनगणना किसी भी देश के विकास की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली अधिकांश योजनाएं, बजट का वितरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, रोजगार सृजन, सडक, बिजली और पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास जनगणना से प्राप्त आंकड़ों पर ही आधारित होता है। यही कारण है कि जनगणना को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) के अंतर्गत किया जाता है। जनसांख्यिकी जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, प्रजनन दर, शिक्षा स्तर, आय, वैवाहिक स्थिति तथा प्रवासन जैसे अनेक पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यही आंकड़े सरकार को यह समझने में सहायता करते हैं कि देश की वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं और किन क्षेत्रों में अधिक निवेश एवं योजनाओं की आवश्यकता है। भारत में जनगणना का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। देश में पहली अस्थायी जनगणना वर्ष 1872 में तत्कालीन वायसराय लार्ड मेयो के समय आयोजित की गई थी। इसके बाद 1881 में लार्ड रिपन के कार्यकाल में पहली नियमित एवं समकालिक जनगणना करवाई गई। तब से लेकर आज तक लगभग प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कार्य किया जाता रहा है। भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में वर्ष 1921 को 'महान विभाजक वर्ष' के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि 1921 की जनगणना में पहली और एकमात्र बार भारत की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके पश्चात देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही और जनसंख्या वृद्धि का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। हालांकि यह

वृद्धि केवल जनसंख्या संख्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात तथा प्रजनन दर जैसे अनेक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतकों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। भारत में जाति आधारित जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। वर्ष 1931 ब्रिटिश शासनकाल की अंतिम प्रकाशित जातिगत जनगणना थी, जिसके आंकड़ों का उपयोग बाद में मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का अनुमान लगाने के लिए किया। वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना करवाई गई, लेकिन उसके सभी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अब लगभग एक शताब्दी बाद वर्ष 2027 की जनगणना में पुनः जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना आयोजित नहीं हो सकी थी, जिससे वर्ष 2027 की जनगणना का महत्व और बढ़ गया है। यह भारत की 16वीं तथा स्वतंत्र भारत की आठवीं जनगणना होगी। इसे दो चरणों में संपन्न किया जाएगा जिसके पहले चरण में आवास संबंधी तथा दूसरे चरण में जनसंख्या संबंधी जानकारी एकत्र की जाएगी। इस जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसका डिजिटल स्वरूप है। पहली बार गणनाकार मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़े दर्ज करेंगे तथा नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। हालांकि इस डिजिटल व्यवस्था के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं।

भगवंत मान अगर सच्चे हैं तो फर्जी रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी : राज्य सभा सांसद रेखा शर्मा

पंजाब के युवा नशे की समस्या में उलझा तो धार्मिक संस्थाओं में हो रहे विवाद

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा की राज्य सभा सांसद रेखा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को विवादित वीडियो के मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि अगर वह सच्चे हैं तो उन्हें फर्जी रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित विधायक दल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में रेखा शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रेखा शर्मा ने कहा कि यदि किसी राज्य को कमजोर करना हो तो उसकी आस्था और उसकी युवा शक्ति पर प्रहार कर दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पंजाब में दोनों ही मोर्चों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक ओर पंजाब का युवा चिट्टा और अन्य नशों की भयावह समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आए तथ्यों और शिकायतकर्ता द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। आरोप है कि 16 जून 2026 को गुरुग्राम स्थित फाइव स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर तथा एसपी का नाम भी सामने आ रहा है, कथित रूप से शामिल थे। रेखा शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक रूप से सामने आए दावों के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो को लेकर एक अनुकूल फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाना था। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बैठक के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं तथा कथित व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं, जिनमें रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में बदलाव, निष्कर्षों को संशोधित करने तथा रिपोर्ट को विशेष दिशा देने संबंधी चर्चाएं दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता जसप्रीत सिंह द्वारा जारी वीडियो में यह दावा किया गया है कि उसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा संपर्क किया गया, गुरुग्राम बुलाया गया और मुख्यमंत्री के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके माध्यम से निजी साइबर विशेषज्ञों से रिपोर्ट तैयार करवाई गई, बाद में उसमें कथित रूप से बदलाव करवाए गए तथा इस कार्य के लिए 10 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन संस्थाओं से रिपोर्ट ली गई, वे सरकारी मान्यता प्राप्त फोरेंसिक प्रयोगशालाएं नहीं थीं। यदि यह सब सत्य है तो यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह है। रेखा शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह विवाद श्री अकाल तख्त साहिब की गरिमा और उसके निर्णयों से जुड़ा हुआ है। श्री अकाल तख्त साहिब सिख पंथ की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है, जिसकी प्रतिष्ठा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। रेखा शर्मा ने कहा कि पंजाब की माताएं आज अपने बच्चों को नशे के कारण खो रही हैं। राज्य के अनेक जिले चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में यदि पुलिस और प्रशासन का ध्यान कानून व्यवस्था, नशा तस्करी और युवाओं को बचाने के बजाए राजनीतिक छवि प्रबंधन में लगा हुआ है, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

पीटीआई भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री रैकेट : मुख्य दलाल पंकज जैन गिरफ्तार

जयपुर (हिंस)। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जी डिग्रियों के जरिए नौकरी दिलाने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसते हुए स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती परीक्षा-2022 में उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी से बैक डेट में फर्जी बीपीएड (बीपीएड) डिग्री दिलाने वाले मुख्य दलाल पंकज कुमार जैन (42) निवासी करवर जिला बूंदी हाल चित्रकूट जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को जयपुर के चित्रकूट क्षेत्र से दबोचा गया है। उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एसओजी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में जेएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) से जारी फर्जी बीपीएड डिग्रियों के मामले में एसओजी ने दर्ज प्रकरण के तहत जांच की जा रही है। जहां जांच में सामने आया कि पंकज कुमार जैन ने अपने सहयोगी पवन सिंह चौहान उर्फ पीएस चौहान के साथ मिलकर भर्ती के एक अभ्यर्थी राजेश कुमार फागणा को फर्जी बीपीएड डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए में सौदा किया था। इसके बाद आरोपी ने जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुकेश कुमार और रजिस्ट्रार नंदन कुमार मिश्रा से मिलीभगत कर पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। बंसल ने बताया कि अभ्यर्थी राजेश फागणा का यूनिवर्सिटी में शिक्षा सत्र 2020-22 में बैक डेट में प्रवेश दर्शाया गया, जबकि उसे सत्र 2017-19 के चारों सेमेस्टर की फर्जी मार्कशीटें जारी कर दी गईं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने शारीरिक शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। एसओजी एडीजी बंसल ने बताया कि इस हाई-प्रोफाइल फर्जी डिग्री रैकेट में जे.एस. यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार समेत तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य दलाल पंकज जैन की गिरफ्तारी के बाद अब जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। एसओजी अब रिमांड अवधि के दौरान यह पता लगाने में जुटी है कि पंकज जैन ने राजस्थान के कितने अन्य अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां दिलवाईं। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में भर्ती घोटाले से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं। एसओजी अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में फर्जी डिग्री रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए उम्मीदों का आकाश खोला : रावत

अजमेर (हिंस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए उम्मीदों का आकाश खोल दिया है, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किशनगढ़ एयरपोर्ट परिसर में स्थित एवियाना एविएशन अकैडमी में प्रशिक्षु पायलेट्स से संवाद करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में भारत में जो विकास हुआ है, वह ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में इन विकास कार्यों का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में किशनगढ़ एयरपोर्ट बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। आने वाले समय में यह एयरपोर्ट राजस्थान के बड़े एयरपोर्ट में गिना जाएगा। ट्रेनी पायलेट्स ने भी बड़े उत्साह से कहा कि पिछले 12 वर्ष में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से काम किए हैं। रावत ने यह भी कहा कि उनके लिए इस अकादमी में आने का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे राजस्थान के युवाओं को नए करियर जैसे एयरक्राफ्ट पायलट, के प्रति जागरूक किया जा सके। इस दौरान रावत ने हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठकर जहाज उड़ाने की पूरी प्रक्रिया जानी, इसके साथ ही जहाज के मेंटेनेंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानकारी भी प्राप्त की। किशनगढ़ एयरपोर्ट के निदेशक बीएस मीणा ने हवाई उड़ान संबंधी समस्त प्रक्रिया से रावत को अवगत कराया। गौरतलब है कि जुलाई, 2024 में शुरू हुई इस अकादमी में 12 सिंगल इंजन और एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट हैं।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के 21 जिलों में किसानों का विरोध प्रदर्शन

कई स्थानों पर केंद्र सरकार और ट्रंप के पुतले फूंके, किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी

चंडीगढ़ (हिंस)। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में बुधवार को किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आया। किसान संगठनों ने पंजाब के 21 जिलों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाले। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले भी फूंके। अमृतसर में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में सैकड़ों किसान भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि इस समझौते को जुलाई के अंत तक लागू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस संबंध में किसानों, खेत मजदूरों और अन्य संबंधित वर्गों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि यदि यह ट्रेड डील लागू होती है तो पंजाब सहित पूरे देश के किसानों, खेत मजदूरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका कहना है कि विदेशी उत्पादों के लिए बाजार खोलने से स्थानीय कृषि और डेयरी क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, मोहाली, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनतारन में प्रदर्शन किए गए। कई स्थानों पर भाजपा कार्यालयों और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों और कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।

योगी सरकार की सौगात : कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर 3446 अभ्यर्थी चयनित

लखनऊ (हिंस)। योगी सरकार में युवाओं को सरकारी सेवा के अपने सपने को पूरा करने का फिर अवसर मिला। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी पद पर 3446 अभ्यर्थियों को चयनित किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 13 जुलाई 2025 को इसकी लिखित परीक्षा कराई थी। मंगलवार (23 जून) को परिणाम घोषित किया गया। कृषि निदेशक रिक्त पदों के अनुरूप जनपदों में इन अभ्यर्थियों को नियुक्त करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के 1813, अनुसूचित जाति के 509, अनुसूचित जनजाति के 151, अन्य पिछड़ा वर्ग के 629, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर 344 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। कृषि सचिव इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि यह भर्ती बहुत समय से प्रतीक्षित थी। अब कृषि विभाग का फील्ड स्तर पर काम और बेहतर हो पाएगा। इससे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में विभाग प्रदेश सरकार को अहम सहयोग दे पाएगा। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमुख सचिव (कृषि) रविंद्र, कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी आदि ने भी शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने सुनाई धार्मिक सजा

चंडीगढ़ (हिंस)। पुलिस कर्मचारियों पर आपत्तिजक टिप्पणी करने के मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को चार धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने की धार्मिक सजा सुनाई है। रवनीत बिट्टू बुधवार को अपने वकीलों के साथ अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी के समक्ष पेश हुए और अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे शब्द 100 फीसदी कानूनी तौर पर गलत थे, जिसके लिए मैंने माफी भी मांगी। बिट्टू ने कहा कि उन्हें सबसे पहले संगरूर में एक एसपी रैंक के अधिकारी ने रोका था। उस अधिकारी ने बताया कि ओएसडी ओंकार को बलिया थाने में हिरासत में रखा गया है। इसके बाद वह बलिया थाने पहुंचे, जहां उन्हें फिर बताया गया कि ओंकार को संगरूर ले जाया गया है।

भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिबियापुर में निकला कैंडल मार्च, सीबीआई जांच की उठी मांग

औरैया (हिंस)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में दिबियापुर मंडी गेट सहायल रोड से फफूंद चौराहे तक मंगलवार देर रात करीब 10 बजे सर्व समाज के लोगों द्वारा विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च बिहार के भोजपुर निवासी भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार और प्रशासन पर भरत तिवारी की सुनियोजित हत्या कराने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च में राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, जन सामान्य मंच सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है,

जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित बृज किशोर तिवारी ने कहा कि भरत तिवारी एक समर्पित समाजसेवी थे। कोरोना काल में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मानवता की रक्षा के लिए वैक्सीन अनुसंधान हेतु अपना शरीर दान करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बिहार से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा भी की थी तथा अपने गांव में सभी वर्गों के हितों के लिए संघर्षरत थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनके परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग भी की गई। कैंडल मार्च में राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सलाहकार पंडित पदम नारायण तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित बृज किशोर तिवारी, जिला अध्यक्ष विवेक दीक्षित, जिला संयोजक रवि तिवारी, समाजसेवी सचिन चोटी वाला, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष शोभित त्रिपाठी, कानपुर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान बिहार सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

सांगानेर को मिली 631 करोड़ रुपए के 1538 विकास कार्यों की सौगात

जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशभर में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ नागरिक सेवाओं के विस्तार पर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना और आमजन को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री बुधवार को सांगानेर स्टेडियम में आयोजित लगभग 631 करोड़ रुपए की लागत के 1538 विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं पट्टा वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन होगा, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक विकसित की जाएगी, जिसके कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो फेज-2 परियोजना से राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और शहर के समग्र शहरी विकास को नई गति मिलेगी। यह परियोजना भविष्य की बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, जिन्होंने शहरों को विकास के इंजन के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूती मिली है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के जरिए *सभी के लिए आवास* के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना ने लाखों रेहड़ी और ठेला संचालकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। वहीं, अमृत योजना के माध्यम से शहरों में पेयजल, सीवरेज कनेक्शन, पार्क और अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार *विकास भी, विरासत भी* के मूलमंत्र पर कार्य करते हुए जयपुर में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बना रही है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल किसानों के लंबित क्लेम का जल्द होगा भुगतान

बीकानेर (हिंस)। जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक के ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड से जुड़े लंबित बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं भाजपा बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया के प्रयास रंग लाए हैं। कृषि विभाग ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए दो अधिकारियों की समिति का गठन किया है, जिससे किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने 29 अप्रैल 2026 को राजस्थान के कृषि आयुक्त नरेश गोयल को लिखित रूप से किसानों की समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कृषि आयुक्त नरेश गोयल से दूरभाष पर वार्ता कर मामले को प्राथमिकता से निस्तारित करने का निर्देश दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि आयुक्त ने दो अधिकारियों की समिति गठित कर लंबित प्रकरणों की जांच एवं शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि किसानों को उनका अधिकार समय पर मिलना चाहिए और किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने कहा कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक उपनिवेशन क्षेत्र के हजारों किसानों का बीमा क्लेम लंबित होने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लोकतंत्र की रक्षा में संघ और सामान्य कार्यकर्ताओं की भूमिका अतुलनीय: सुनील आंबेकर

पटना (हिंस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि वर्ष 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यह केवल राजनीतिक असहमति को दबाने का प्रयास नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष, जन-जागरण और लोकतंत्र के प्रति जनता की प्रतिबद्धता के कारण मात्र 19 महीनों में तानाशाही प्रवृत्तियों को परास्त कर देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना संभव हो सकी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को पटना में *हिंदुस्थान समाचार समूह* द्वारा आयोजित *बिहार आंदोलन और आपातकाल* विषयक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंबेकर ने कहा कि देश में भविष्य में कभी भी आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन कारणों और शक्तियों की पहचान करना आवश्यक है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्र हुए उस समय मात्र 25 वर्ष ही हुए थे। वर्ष 1947 में आजादी मिलने, 1950 में संविधान लागू होने और 1952 में पहले आम चुनाव संपन्न होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी पूरी तरह मजबूत भी नहीं हो पाई थी कि तानाशाही प्रवृत्तियों ने लोकतंत्र को चुनौती दे दी। इसका परिणाम 25 जून, 1975 को लगाए गए आपातकाल के रूप में सामने आया। आंबेकर ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में जब भी तानाशाही शासन स्थापित हुआ, वह दो से ढाई दशकों तक बना रहा। भारत में भी आपातकाल लागू करने वालों की सोच और योजना दीर्घकालिक थी, लेकिन भारतीय समाज की लोकतांत्रिक चेतना और जनता के व्यापक प्रतिरोध ने उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध हुआ संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इसमें समाज के सभी वर्गों, विचारधाराओं और संगठनों के लोगों ने भागीदारी निभाई। यह किसी एक दल या संगठन का आंदोलन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे राष्ट्र का सामूहिक संघर्ष था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रश्न उठाया कि एक गैर-राजनीतिक संगठन होने के बावजूद संघ को निशाना क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही तत्कालीन सरकार की

गतिविधियों और दृष्टिकोण से यह स्पष्ट था कि वह संघ को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती थी, जबकि संघ स्वयं को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में संचालित करता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को आशंका थी कि संघ की उपस्थिति में उसकी मनमानी नहीं चल सकेगी। इसी कारण संघ को समाप्त करने की मानसिकता पहले से मौजूद थी और राजनीतिक कारणों से संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि प्रतिबंध, गिरफ्तारियों और दमनात्मक कार्रवाइयों के बावजूद संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। आंबेकर ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में संघ ने देशभर में जो वैचारिक आधार और संगठनात्मक तंत्र विकसित किया था, उसी के कारण आपातकाल के दौरान व्यापक जन-जागरण संभव हो सका। जब विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जेलों में बंद थे, तब संघ के हजारों सामान्य कार्यकर्ताओं ने आंदोलन और जनसंपर्क की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बताया कि ऐसे अनेक कार्यकर्ता थे जिन्हें सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोकतंत्र की रक्षा का संदेश पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत पहचान, पद या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के इन कार्यकर्ताओं ने आपातकाल का विरोध किया और जनता को जागरूक बनाने का कार्य किया। यही जमीनी संघर्ष आगे चलकर एक व्यापक जन-आंदोलन में परिवर्तित हुआ। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए इसी राष्ट्रव्यापी संघर्ष का परिणाम था कि मात्र 19 महीनों के भीतर आपातकाल समाप्त हुआ और भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संवैधानिक व्यवस्था की गौरवपूर्ण पुनर्स्थापना सुनिश्चित हो सकी। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बिहार आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व और आपातकाल विरोधी संघर्ष के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने आपातकाल के अनुभवों से सीख लेते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति सतत सजग रहने का आह्वान किया।

कमजोर मानसून बड़ी चुनौती : देश पर सूखे का साया, 22 दिनों में सामान्य से 43 फीसदी कम बारिश; महंगाई बढ़ने का खतरा

नई दिल्ली

दक्षिण-पश्चिम मानसून का पहला महीना खत्म होने में सिर्फ एक सप्ताह बचा है, लेकिन अब तक बीता यह सीजन देश के अन्नदाताओं और अर्थव्यवस्था के लिए सूखे जैसी बड़ी चुनौती लेकर आया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, एक से 22 जून तक देशभर में सामान्य से 43 फीसदी कम बारिश हुई है।मानसून की स्थिति में अगर तुरंत सुधार नहीं हुआ, तो देश के प्रमुख कृषि राज्यों में खरीफ की खेती पर तगड़ी मार पड़ सकती है। इससे न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में मांग प्रभावित होगी, बल्कि खाद्य महंगाई का खतरा भी तेजी से बढ़ेगा। दरअसल, देश में सबसे ज्यादा खरीफ उत्पादन करने वाले महाराष्ट्र में सामान्य से 82 फीसदी और गुजरात में 75 फीसदी कम बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में 69 फीसदी और मध्य प्रदेश में 52 फीसदी कम बरसात दर्ज की गई है। वहीं, झारखंड में सामान्य से 66 फीसदी, ओडिशा में 48 फीसदी और बिहार, उत्तर प्रदेश एवं तेलंगाना में 43-43 फीसदी कम पानी बरसा है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में 40 फीसदी और केरल में 28 फीसदी कम बारिश हुई है।

खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा असर : शिवराज - भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 2 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह तक मानसून ऐसे ही कमजोर रह सकता है।इसका असर खरीफ फसलों और संवेदनशील इलाकों पर पड़ेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के 315 जिलों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है।इससे खरीफ फसलों की बुवाई पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। देश में अब तक कुल खरीफ क्षेत्र का करीब 10 फीसदी हिस्सा ही बोया गया है। 22 जून तक खरीफ फसलों का कुल रकबा 1.17 करोड़ हेक्टेयर रहा।हालांकि, यह पिछले वर्ष की समान अवधि (1.13 करोड़ हेक्टेयर) से थोड़ा अधिक है, लेकिन पानी की कमी से आगे की बुवाई और बोई जा चुकी फसलों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।

देश के 315 जिलों में सामान्य से कम बारिश - सरकार ने 111 जिलों को अति-संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। यानी इन जिलों में कमजोर मानसून की सबसे अधिक मार पड़ेगी, क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधा 25 फीसदी से भी कम है और वे बारिश पर ही निर्भर हैं। इनमें अकेले 20 जिले सिर्फ महाराष्ट्र में हैं।

आरबीआई की बड़ी चेतावनी - आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जोपिछले वित्त वर्ष के 7.7 फीसदी से कम है।

न्यूज ब्रीफ

भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए 15 जुलाई से होगा लागू, सस्ती होंगी कारें

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का असर अब आटोमोबाइल क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन से भारत आयात की जाने वाली कुछ प्रीमियम और लक्जरी कारों पर लगने वाले शुल्क में राहत मिलने की संभावना है, जिसके चलते कई लोकप्रिय माडलों की कीमतों में कमी आ सकती है। जानकारी के अनुसार, इस नई व्यवस्था को 15 जुलाई से लागू किया जा सकता है। वर्तमान में विदेशों से आयात की जाने वाली लक्जरी कारों पर भारत में भारी आयात शुल्क लगाया जाता है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में काफी महंगी हो जाती हैं। नए समझौते के बाद इस शुल्क में कमी आने से कार निर्माताओं की लागत घटेगी, जिसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलने की उम्मीद है। हालांकि प्रत्येक माडल पर कीमत में समान कमी नहीं होगी, लेकिन कई गाड़ियों के मूल्य में लाखों रुपये तक का अंतर आने की संभावना जताई जा रही है। आटोमोबाइल उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि शुल्क में राहत मिलने के बाद कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन करेंगी, जिससे लक्जरी वाहन बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और ग्राहकों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जगुआर जैसे माडलों की कीमतों में कमी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कीमतों में कमी से केवल ग्राहकों तक ही नहीं, बल्कि पूरे लक्जरी वाहन बाजार को भी गति मिल सकती है, जिससे बिक्री में वृद्धि होगी।

ईंधन खुदरा विक्रेताओं को मार्जिन में राहत, पर कर अनिश्चितता बनी चुनौती

मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ईंधन विपणन कंपनियों (ओएमसी) के मार्जिन में सुधार हुआ है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली है। हालांकि, रिपोर्ट ने बढ़ते कर्ज के बोझ और ईंधन पर कर नीति को लेकर अनिश्चितता के कारण इस क्षेत्र की दीर्घकालिक कमाई की संभावनाओं को सीमित बताया है। रिपोर्ट बताती है कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी और केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के चलते सरकारी तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल और डीजल बिक्री पर संयुक्त मार्जिन अब पश्चिम एशिया संघर्ष-पूर्व स्तर से ऊपर पहुँच गया है। संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के बावजूद देश में खुदरा कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। एलपीजी पर होने वाला नुकसान भी तेल कीमतों में गिरावट के साथ जल्द ही कम होने की उम्मीद है, जिससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति में और सुधार होगा। हालांकि, रिपोर्ट ने मार्जिन में इस सुधार को लेकर सतर्कता बरती है। पिछले कुछ महीनों में ओएमसी पर काफी कर्ज चढ़ा है, जिससे उनके मूल्यांकन पर असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त, लाभ का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा मार्च में की गई 10 रुपये प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क कटौती के कारण है, जो वैश्विक तेल कीमतें स्थिर होने पर भविष्य में फिर से लगाया जा सकता है।

कुणाल शाह को मिली व्हाट्सऐप की ग्लोबल कमान, रचा इतिहास!

नई दिल्ली। टेक उद्योग में एक बड़े फेरबदल के तहत फिनटेक प्लेटफार्म सीआरईडी के संस्थापक और प्रमुख उद्यमी कुणाल शाह को मैसेजिंग दिग्गज व्हाट्सऐप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति तब हुई है जब फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफार्म्स ने शाह की ही कंपनी क्रेड में 90 करोड़ रुपए (900 मिलियन डालर) के एक रणनीतिक निवेश की घोषणा की है। शाह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जो वैश्विक टेक परिदृश्य में देश के बढ़ते प्रभाव और भारतीय नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। वह 2019 से व्हाट्सऐप का नेतृत्व कर रहे विल कैथकार्ट की जगह लेंगे, जो अब मेटा के भीतर अगली पीढ़ी के उत्पाद विकास पर केंद्रित एक नए डिवीजन की कमान संभालेंगे। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब मेटा प्लेटफार्म्स ने क्रेड में 90 करोड़ डालर (900 मिलियन डालर) निवेश करने का फैसला किया है। इस रणनीतिक निवेश के तहत मेटा को क्रेड में 20 फीसदी अल्पांश हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे इस सौदे के बाद क्रेड का मूल्यांकन 4.5 अरब डालर लगभग 43,239 करोड़ रुपये आंका गया है।

सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे में सुधार की उम्मीद कच्चे तेल की घटती कीमतों से ईंधन विपणन मार्जिन बेहतर होने का अनुमान

नई दिल्ली

सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए मुनाफे में सुधार की उम्मीद जगी है। जेपी मार्गन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की घटती कीमतों से ईंधन विपणन मार्जिन में सुधार इसका मुख्य कारण है। हालांकि, बढ़ते कर्ज और ईंधन कर को लेकर अनिश्चितता इस क्षेत्र की लंबी अवधि की कमाई की संभावनाओं को सीमित कर सकती है।

जेपी मार्गन की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी रिफाइनरियों और खुदरा ईंधन विक्रेताओं के पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर संयुक्त मार्जिन अब पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर से ऊपर है। यह कच्चे तेल की कम कीमतों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती का परिणाम है। संघर्ष के दौरान वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद घरेलू कीमतें स्थिर रहने से कंपनियों को घाटा हुआ था, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है।

एलपीजी पर अभी भी नुकसान अधिक है, लेकिन तेल कीमतों के साथ इसमें भी कमी आने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में माल भंडार के नुकसान का असर दिखेगा, लेकिन दूसरी तिमाही में लाभ बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, मार्जिन सुधार को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। ओएमसी पर काफी कर्ज चढ़ा है, जिससे मूल्यांकन प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण है, और भविष्य में इसके फिर से बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। सरकार कर्ज चुकाने में ओएमसी की मदद के लिए कुछ समय तक कर कम रख सकती है, लेकिन अनिश्चितता बरकरार है। अगर तेल कीमतें कम रहती हैं, तो भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) को निकट भविष्य में सबसे अधिक लाभ होने का अनुमान है।

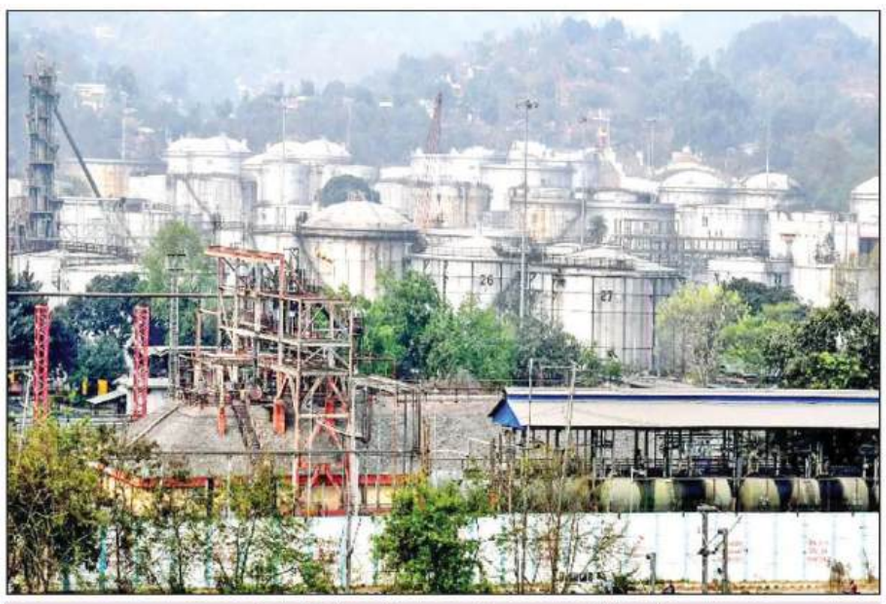

अगले महीने कई एसयूवी माडल होंगे लांच

नई दिल्ली। भारतीय आटोमोबाइल बाजार में अगले महीने कई दमदार एसयूवी लान्च होने वाली हैं। इन एसयूवी में शानदार रोड प्रेजेंस और बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, स्कोडा 22 जून 2026 को नई स्कोडा कोडिएक आरएस लान्च करने जा रहा है। यह कंपनी की परफार्मेंस-ओरिएंटेड एसयूवी होगी, जिसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 263 हार्सपावर की पावर और 400 एनएम का टार्क जेनरेट करेगा। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसके बाद, टाटा मोटर्स अपनी सिएरा ईवी को 30 जून 2026 को लान्च करेगी। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सिएरा ईवी का डिजाइन इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन जैसा ही रहने की उम्मीद है, जिसमें ऊंचा स्टांस और रगेड एसयूवी लुक होगा। यह कंपनी के एक्टी.ईवी+ प्लेटफार्म पर आधारित होगी और इसमें 55 केडब्ल्यूएच और 65 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के विकल्प मिल सकते हैं, साथ ही सिंगल मोटर और ड्यूल मोटर, तथा टाप वेरिएंट में आल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) सिस्टम भी दिया जा सकता है। वहीं, निसान अपनी नई मिड-साइज एसयूवी टेक्टान को 9 जुलाई 2026 को इंडियन मार्केट में उतारेगी। यह एसयूवी रेनो डस्टर का रीबैज्ड वर्जन होगी, जो आरजीएमपी प्लेटफार्म पर आधारित रहेगी। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रान्ग हाइब्रिड इंजन जैसे विकल्प मिलने की उम्मीद है, साथ ही मैनुअल और आटोमैटिक दोनों गियरबाक्स आप्शन भी मिलेंगे। और अंत में, होंडा ने मई में भारत में अपनी नई जेडआर-वी एसयूवी को पेश किया था, जिसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसकी कीमतों की घोषणा जुलाई में होने की उम्मीद है और इसी दौरान इसकी डिलीवरी भी शुरू हो सकती है।

नया इलेक्ट्रिक स्कूटर डेफी 22 पेश, जबर्दस्त माइलेज का दावा

नई दिल्ली

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी फेराटो ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, डेफी 22, पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार पूर्ण रूप से चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक की वास्तविक दूरी तय कर सकता है, जो इसे शहरी और अर्ध-शहरी उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।

फेराटो डेफी 22 को कई आकर्षक द्वि-रंगी रंग विकल्पों में उपलब्ध कराया गया है, जिनमें शैंपेन क्रीम, ब्लैक फायर, कोस्टल आइवरी, यूनिटी व्हाइट, रेजिलिएंस ब्लैक, डब ग्रे और मैट ग्रीन जैसे रंग शामिल हैं। इस स्कूटर में 2.2 किलोवाट-घंटा क्षमता की लिथियम फेरो फास्फेट बैटरी दी गई है, जिसके साथ 1200 वाट की विद्युत मोटर जोड़ी गई है, जो आवश्यकता पड़ने पर 2500 वाट तक की अधिकतम शक्ति उत्पन्न कर सकती है। स्कूटर की अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, जो शहरों में नियमित उपयोग के लिए पर्याप्त है। फेराटो ने इस स्कूटर में आधुनिक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा है; इसमें सात इंच का स्पर्श आधारित डिजिटल प्रदर्शन पटल दिया गया है, जो वाहन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है, साथ ही इसमें संगीत सुविधा भी शामिल है। स्कूटर में 12 इंच के आकर्षक मिश्रधातु पहिए दिए गए हैं। कंपनी ने डेफी 22 में सुरक्षा को भी महत्व दिया है, जिसमें संयुक्त डिस्क ब्रेक प्रणाली और बैटरी को धूल व पानी से सुरक्षा देने वाली विशेष श्रेणी शामिल है। भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के बीच, फेराटो ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,01,999 रुपये रखी है, जिससे यह मध्यम बजट के ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। बता दें कि आकर्षक डिजाइन, आधुनिक तकनीक और लंबी दूरी तय करने की क्षमता के साथ आया यह स्कूटर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो दैनिक आवागमन के लिए किफायती और सुविधाजनक विकल्प की तलाश कर रहे हैं।

दो लाख डाउन पेमेंट पर स्कोडा काइलाक आटोमैटिक

नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी स्कोडा की ओर से काइलाक का क्लासिक एटी वेरिएंट आटोमैटिक विकल्प के रूप में आफर किया गया है। अगर आप स्कोडा काइलाक के आटोमैटिक वेरिएंट को दो लाख रुपये का डाउन पेमेंट करके खरीदते हैं, तो आपको लगभग 8.30 लाख रुपये की राशि बैंक से फाइनेंस करवानी होगी। इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 9.25 लाख रुपये है। दिल्ली में इसे खरीदने पर लगभग 65 हजार रुपये आरटीओ और करीब 40 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे, जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में आन-रोड कीमत 10.30 लाख रुपये हो जाती है। यदि बैंक नौ फीसदी वार्षिक ब्याज दर के साथ सात साल के लिए यह लोन देता है, तो आपको हर महीने सिर्फ 13,355 रुपये की मासिक किस्त (ईएमआई) देनी होगी। इस गणना के अनुसार, सात साल की अवधि में आप स्कोडा काइलाक के आटोमैटिक वेरिएंट के लिए लगभग 2.91 लाख रुपये बतौर ब्याज चुकाएंगे। इस तरह, आपकी गाड़ी की कुल लागत (एक्स-शोरूम कीमत, आन-रोड शुल्क और ब्याज मिलाकर) लगभग 13.21 लाख रुपये हो जाएगी।

सर्राफा बाजार में फीकी पड़ी सोने की चमक, चांदी के भाव में भी गिरावट

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आई कमजोरी के कारण चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर दूसरे सर्राफा बाजार में सोना 1,770 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,930 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। वहीं, चेन्नई में सोने के भाव में 400 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 440 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आई है। चांदी के भाव में भी 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। सोने की कीमत में आई कमजोरी के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,44,590 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,47,920 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,32,540 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,35,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,44,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,44,590 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,44,640 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,590 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,47,920 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,35,590 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,44,590 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,44,740 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,44,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,32,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,44,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,32,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जान्स फ्यूचर्स सपाट स्तर पर मामूली कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान सेमीकंडक्टर स्टाक्स में आई जोरदार गिरावट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रवैये को लेकर बने चिंता की वजह से गिरावट के साथ बंद हुए।

डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज इस 0.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 51,665.49 अंक के स्तर पर आ गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 107.33 अंक यानी 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,365.46 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 545.30 अंक यानी 2.08 प्रतिशत टूट कर 25,621.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 51,663.58 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान कमजोरी के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.09 प्रतिशत लुढ़क कर 10,428.85 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.71 प्रतिशत फिसल कर 8,340.71 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 246.11 अंक यानी 0.99 प्रतिशत टूट कर 24,893.58 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक कमजोरी के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि चार सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। कोस्पी इंडेक्स फिलहाल 92.81 अंक यानी 1.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ 8,296.65 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,406 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा, गिफ्ट निफ्टी 0.25 प्रतिशत की उछाल के साथ 23,869.50 अंक के स्तर पर और स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,216.41 अंक के स्तर पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी ओर, निक्केई इंडेक्स 688.38 अंक यानी 0.99 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 69,100 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.25 प्रतिशत फिसल कर 4,096.14 अंक के स्तर पर आ गया है। ताइवान वेटेड इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 1,136.78 अंक यानी 2.47 प्रतिशत लुढ़क कर 45,963.87 अंक के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 1.06 प्रतिशत टूट कर 6,037.56 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,540.29 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

हाकी इंडिया ने ब्रिटेन दौरे के लिए की 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला टीम की घोषणा

नई दिल्ली

हाकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक होने वाले ब्रिटेन दौरे के लिए बुधवार को 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हाकी टीम की घोषणा कर दी है। नए मुख्य प्रशिक्षक टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में टीम स्काटलैंड और इंग्लैंड में कुल सात मुकाबले खेलेगी। यह दौरा आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विशेषकर जूनियर एशिया कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

टीम की कप्तानी खैदेम शिलेइमा चानू को सौंपी गई है। गोलकीपर के रूप में निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज को टीम में शामिल किया गया है।

दौरे की शुरुआत एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में स्काटलैंड की सीनियर महिला टीम के खिलाफ दो मुकाबलों से होगी। इसके बाद भारतीय टीम लिलेशाल राष्ट्रीय खेल केंद्र में अमेरिका, इंग्लैंड और बेल्जियम की जूनियर टीमों के खिलाफ मैच खेलेगी। मुख्य प्रशिक्षक टिम व्हाइट ने टीम चयन और दौरे के महत्व पर कहा, ब्रिटेन दौरा हमारी जूनियर टीम के विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने कई ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें विदेशी टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव नहीं है। ऐसे में यह दौरा खिलाड़ियों और पूरी टीम दोनों के लिए सीखने का बेहतरीन अवसर होगा। उन्होंने आगे कहा, हमें मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। पिछले दस सप्ताह से जिस खेल शैली पर हमने काम किया है, उसे मैदान पर लागू करने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह दौरा जूनियर एशिया कप की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इससे हमें अपनी ताकत तथा सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों का बेहतर आकलन करने का अवसर मिलेगा।

भारतीय जूनियर महिला टीम

गोलकीपर: निधि, एंगिल हर्षा रानी मिंज।

डिफेंडर्स : पूजा साहू, सुप्रिया, मधु, एफ. लालबी अक्सियामी, लालनेहपुई, पार्वती टोपनो।

मिडफील्डर: खैदेम शिलेइमा चानू (कप्तान), तनुजा टोप्पो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, बिनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद, तनुश्री दिनेश कडू।

फारवर्ड: सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिनपुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल, सानिका चंद्रकांत माने, कृष्णा शर्मा।

न्यूज ब्रीफ

आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप : वंशिका और शिवा ने जीता रजत, भारत शीर्ष पर बरकरार

नई दिल्ली। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत की वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की झोली में एक और पदक डाल दिया। भारतीय जोड़ी ने पूरे मुकाबले के दौरान संयमित और प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और अंततः रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ भारत ने प्रतियोगिता में एक और महत्वपूर्ण पदक जोड़ लिया। इस पदक के बाद आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत की कुल पदक संख्या 16 हो गई है। भारतीय दल के खाते में अब 5 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय दल पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारतीय निशानेबाजों की निरंतर सफलता ने एक बार फिर विश्व मंच पर देश की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। राष्ट्रीय राइफल संघ ने भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि युवा निशानेबाजों का यह प्रदर्शन भविष्य के लिए उत्साहजनक संकेत है और भारतीय निशानेबाजी की मजबूत प्रतिभा को दर्शाता है ।

फीफा विश्व कप 2026 : घाना की मजबूत रक्षा के आगे बेबस हुआ इंग्लैंड, खेला गोलरहित ड्रा

मैसाचुसेट्स। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप एल मुकाबले में घाना ने शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। बोस्टन स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ियों के कई प्रयास घाना की सुदृढ़ रक्षा पंक्ति के सामने नाकाम रहे। हैरी केन और जूड बेलिंगहम की अगुवाई में इंग्लैंड ने पूरे मैच में आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन घाना के खिलाड़ियों ने अनुशासित खेल दिखाते हुए कोई मौका नहीं दिया। इस ड्रा के साथ घाना के दो मैचों में चार अंक हो गए हैं और वह केवल बेहतर गोल अंतर के आधार पर इंग्लैंड से पीछे है। इंग्लैंड को मैच जीतने का सबसे बड़ा अवसर निर्धारित समय के अंतिम क्षणों में मिला। स्थानापन्न खिलाड़ी निको ओराइली ने दाएं छोर से आए क्रास पर शानदार हेडर लगाया, लेकिन गेंद गोलपोस्ट से टकराकर वापस आ गई। इसके बाद मिले मौके पर हैरी केन भी गेंद को गोल में नहीं पहुंचा सके और उनका शाट बार के ऊपर चला गया। दूसरे हाफ में इंग्लैंड के मुख्य प्रशिक्षक थामस टुखेल ने आक्रामकता बढ़ाने के लिए मार्गन रोजर्स और एबेरेची एज़े को मैदान पर उतारा, लेकिन इससे भी टीम के खेल में कोई खास बदलाव नहीं आया।

फीफा विश्व कप 2026 : पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से रौंदा रोनाल्डो ने दागे दो गोल

ह्यूस्टन। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल दागकर अपनी टीम को फीफा विश्व कप 2026 में

उज्बेकिस्तान पर 5-0 की एकतरफा जीत दिलाई। इस शानदार जीत के साथ पुर्तगाल नाकआउट चरण में पहुंचने के बेहद करीब पहुंच गया है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने मुकाबले के छठे मिनट में गोल कर इतिहास रच दिया। वह विश्व फुटबाल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने छह अलग-अलग विश्व कप अभियानों में गोल करने का कारनामा किया है। उनका यह सफर 2006 विश्व कप से शुरू हुआ था। रोनाल्डो ने गोल करने के बाद अपना प्रसिद्ध सियू उत्सव मनाया और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का अभिवादन किया। इसके बाद नूनो मेंडेस ने 17वें मिनट में फ्री किक पर गोल कर पुर्तगाल की बढ़त 2-0 कर दी। रोनाल्डो ने 39वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागकर टीम को 3-0 की मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ उनके विश्व कप में कुल 10 गोल हो गए, जो किसी भी पुर्तगाली खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक गोल हैं। उज्बेकिस्तान की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई। इटली के पूर्व विश्व कप विजेता फाबियो कानावारो के मार्गदर्शन में खेल रही टीम पुर्तगाल के आक्रामक खेल का मुकाबला नहीं कर सकी। पहले हाफ में ही पुर्तगाल को चौथा गोल मिला, जब एक कार्नर के दौरान गेंद उज्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोखिद नेमातोव से टकराकर गोल में चली गई ।

स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए उपलब्ध हैं नेमार, लेकिन खेलना तय नहीं : कोच अंचेलोटी

मियामी

ब्राज़ील के मुख्य कोच कार्लो अंचेलोटी ने मंगलवार को पुष्टि की है कि स्टार फुटबालर नेमार स्काटलैंड के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-सी मुकाबले के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें अंतिम एकादश में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। 34 वर्षीय नेमार को लगभग तीन वर्ष बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका मिला है। हालांकि पिंडली की चोट के कारण वह अभी तक इस विश्व कप में मैदान पर नहीं उतर सके हैं। मुकाबले से पहले आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अंचेलोटी ने कहा, नेमार उपलब्ध हैं। उन्होंने इस सप्ताह अच्छी तरह अभ्यास किया है और मैच के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी से हम बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, मैंने उन्हें करीब से जाना है। उन्होंने चोट से जल्द उबरने के लिए बेहद गंभीरता से मेहनत की है। यदि वह मैदान पर नहीं भी उतरते हैं, तब भी उनका अनुभव और खेल की समझ युवा खिलाड़ियों की मदद करती है। नेमार के खेलने की संभावित अवधि के बारे में पूछे जाने पर अंचेलोटी ने मजाकिया अंदाज में कहा, वह 90 मिनट खेल सकते हैं, लेकिन चलते हुए। वह पूरी तरह फिट हैं और उन्होंने शानदार अभ्यास किया है। ब्राज़ील ने अपने पहले दो मुकाबलों में मोरक्को से 1-1 की बराबरी की थी और हैती को 3-0 से हराया था। स्काटलैंड के खिलाफ जीत मिलने पर टीम अंतिम 32 में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी। अंचेलोटी ने कहा, पहला मैच हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था, दूसरा उससे बेहतर रहा। हमें विश्वास है कि तीसरा मुकाबला अब तक का सबसे अच्छा होगा। ब्राज़ील को इस मैच में राफिन्हा की कमी भी खलेगी, जो हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए हैं। हालांकि अंचेलोटी ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनकी जगह शुरुआती एकादश में कौन खेलेगा। स्काटलैंड के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, स्काटलैंड एक मजबूत और अनुशासित टीम है। उनके पास अनुभवी खिलाड़ी हैं और वे संघर्ष करना जानते हैं। विश्व कप में अब कोई भी मुकाबला आसान नहीं होता, इसलिए हम एक कठिन चुनौती के लिए तैयार हैं। ब्राज़ील की टीम न्यू जर्सी से मियामी पहुंचने में देरी का सामना कर रही थी, जिसके कारण अंचेलोटी का संवाददाता सम्मेलन भी देर से हुआ।

पांड्या के मुम्बई छोड़कर केकेआर या रायल्स जाने की संभावना

मुम्बई । आलराउंडर हार्दिक पांड्या अब इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में मुमबई इंडियंस में नजर नहीं आयेंगे। हार्दिक के अगले सत्र में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) या राजस्थान रायल्स से खेलने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार केकेआर और रायल्स ट्रेड डील के जरिये पांड्या को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। मुम्बई को उनके संभावित ट्रेड के लिए कम से कम दो टीमों से प्रस्ताव मिले हैं। माना जा रहा है कि केकेआर प्रबंधन और मुंबई इंडियंस के मालिकों के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली को को लेकर कई दौर की बातचीत भी हुई है। आईपीएल के 19 वें सत्र में पांड्या का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था जिस कारण मुम्बई भी अब उन्हें टीम में बनाये नहीं रखना चाहती। वहीं पिछले दो सत्र से खराब प्रदर्शन से परेशान केकेआर हार्दिक को अपनी टीम में लाने को लेकर सभी प्रयास कर रही है। वह उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी देना चाहती है।, इसका कारण है कि अभी टीम उपकप्तान रिंकू सिंह को कप्तानी के लिए सही नहीं मानती। अभी टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के पास है पर उनके रहते टीम का प्रदर्शन अच्छ नहीं रहा है। केकेआर रहाणे को टीम से रिलीज करना चाहती है। केकेआर के अधिकारियों ने पिछले सत्र में भी मुम्बई से संपर्क किया था, पर उस समय रिलायंस की वार्षिक आम बैठक के कारण फ्रैंचाइजी बात नहीं कर पायी थी। वहीं दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस को राजस्थान रायल्स से भी एक प्रस्ताव मिला है, जिसमें पांड्या और यशस्वी जायसवाल के बीच ट्रेड-आफ की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह बातचीत कहां तक पहुंची है। गौरतलब है कि राजस्थान रायल्स रियान पराग को कप्तानी देना चाहते हैं। ऐसे में हार्दिक के लिए वहां रायल्स में कप्तानी हासिल करना कठिन होगा।

फीफा विश्व कप 2026 : मुन्योज़ के गोल से कोलंबिया नाकआउट चरण में, डीआर कांगो को 1-0 से हराया

न्यूयार्क/न्यू जर्सी

डेनियल मुन्योज़ के दूसरे हाफ में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत कोलंबिया ने फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-के मुकाबले में बुधवार को डीआर कांगो को 1-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। लगातार दूसरी जीत के साथ कोलंबिया ने छह अंक जुटा लिए और एक मैच शेष रहते नाकआउट चरण का टिकट हासिल कर लिया।

मुकाबले में कोलंबिया ने शुरुआत से ही गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और कई मौके भी बनाए, लेकिन डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेम्स रोड्रिगेज, लुइस डियाज और जान एरियास के प्रयासों को विफल कर दिया।

पहले हाफ में कोलंबिया को बढ़त नहीं मिल सकी और डीआर कांगो की रक्षापंक्ति लगातार दबाव झेलते हुए भी गोल बचाने में सफल रही।

आखिरकार 76वें मिनट में कोलंबिया को सफलता मिली। हुआन क्विंटेरो के सटीक पास पर डेनियल मुन्योज़ दाएं छोर से तेजी से पेनाल्टी क्षेत्र में पहुंचे और उनका निचला शाट एक रक्षक से हल्का सा टकराकर गोल में चला गया। यही गोल मुकाबले का फैसला साबित हुआ।

डीआर कांगो ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन कोलंबियाई रक्षा पंक्ति ने उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं दिया।

इस जीत के साथ कोलंबिया छह अंकों के साथ नाकआउट चरण में पहुंच गया है। अब उसका अंतिम ग्रुप मुकाबला पुर्तगाल से होगा। दूसरी ओर डीआर कांगो के खाते में दो मैचों के बाद केवल एक अंक है और उसे अपनी उम्मीदें जीवित रखने के लिए अंतिम मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी।

कोलंबिया ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाया, जबकि डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी की शानदार बचावों के कारण मुकाबला लंबे समय तक गोलरहित बना रहा। हालांकि अंत में मुन्योज़ के गोल ने दक्षिण अमेरिकी टीम को बहुमूल्य जीत दिला दी।

सूर्यांश ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया

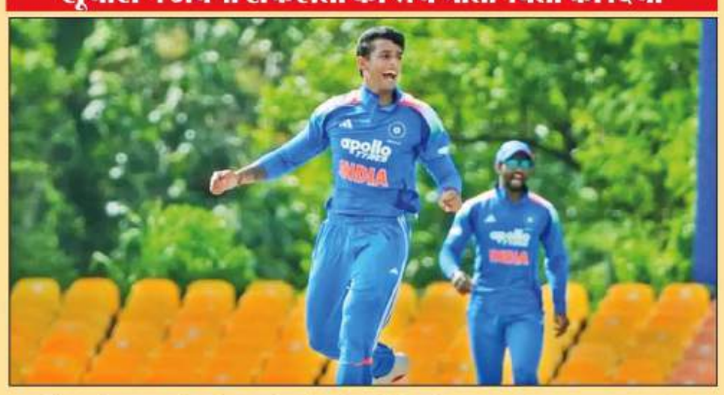

मुम्बई। पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किये गये 23 साल के आलराउंडर सूर्यांश शेडगे की खुशी का ठिकाना नहीं है। सूर्यांश को आलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के चोटिल होने के कारण आयरलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए शामिल किया गया है। सूर्यांश को पिछले दो साल में घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और भारत ए टीम की ओर से लगातार किये अच्छे प्रदर्शन का लाभ मिला है।सूर्यांश के अनुसार उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि वह टीम में शामिल कर लिए गये हैं। इससे उनका बचपन का सपना भी पूरा हो गया है। इस आलराउंडर ने अपनी । सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को दिया है। साथ ही कहा कि उनके बिना कभी ये संभव नहीं होता। सूर्यांश के क्रिकेटर बनने में मां का विशेष योगदान रहा है। उनकी मां एक बैंक में काम करती थीं पर उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेट करियर को देखते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपना पूरा समय सूर्यांश के अभ्यास, मैचों और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जरूरत पर लगाया जिससे कि सूर्यांश खेल पर पूरा ध्यान दे सकें। इसी का परिणाम है कि आज सूर्यांश भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इसके पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे, मनीष बांगेरा और मोंटी देसाई जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस क्रिकेटर की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महिला टी20 विश्व कप : आस्ट्रेलिया की लगातार चौथी जीत, पाकिस्तान को 113 रन से रौंदा

लीड्स

एलिस पेरी की शानदार अर्धशतकीय पारी और घातक गेंदबाजी के दम पर आस्ट्रेलिया ने मंगलवार देर रात महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान को 113 रन से करारी शिकस्त देकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ आस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है, जबकि पाकिस्तान को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा।

पहले बल्लेबाजी करते हुए आस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 13.4 ओवर में मात्र 86 रन पर सिमट गई।

आस्ट्रेलिया की शुरुआत झटके के साथ हुई जब बेथ मूनी बिना खाता खोले आउट हो गईं, लेकिन इसके बाद एलिस पेरी और जार्जिया वोल ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए

100 रन की साझेदारी की। पेरी ने 48 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक शाट शामिल रहे। जार्जिया वोल ने 39 रन का योगदान दिया।

पाकिस्तान की ओर से नशरा संधू और सादिया इकबाल ने दो-दो विकेट लिए, लेकिन आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बड़े स्कोर से नहीं रोक सकीं।

200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ही ओवर में गुल फिरोजा रन आउट हो गईं। पाकिस्तान की पारी में कुल तीन बल्लेबाज रन आउट हुए, जिससे टीम कभी मुकाबले में लौट नहीं सकी। मुनीबा अली ने 32 रन और फातिमा सना ने 17 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके।

एलिस पेरी ने बल्ले के बाद गेंद से भी कमाल दिखाया और केवल एक ओवर में 9 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। सोफी मोलिन्यू ने 6 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि एनाबेल सदरलैंड ने भी दो सफलताएं हासिल कीं।

पाकिस्तान की टीम 86 रन पर ढेर हो गई और आस्ट्रेलिया ने मुकाबला 113 रन से जीत लिया।

अब आस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला भारत से होगा, जबकि पाकिस्तान अपनी पहली जीत की तलाश में नीदरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगा।

संक्षिप्त स्कोर:

आस्ट्रेलिया - 199/7 (20 ओवर)
एलिस पेरी 71, जार्जिया वोल 39
नशरा संधू 2/33, सादिया इकबाल 2/31

पाकिस्तान - 86 आल आउट (13.4 ओवर)
मुनीबा अली 32, फातिमा सना 17
सोफी मोलिन्यू 2/6, एलिस पेरी 2/9

परिणाम: आस्ट्रेलिया 113 रन से विजयी।

विंबलडन 2026 के ऐतिहासिक आगाज़ के लिए तैयार सिनर और स्वियातेक

जिनेवा

विश्व के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2026 का आगाज इस बार एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। गत पुरुष एकल चैंपियन यानिक सिनर 29 जून को सेंटर कोर्ट पर पहला मुकाबला खेलेंगे और ऐसा करने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन जाएंगे।

पिछले वर्ष पुरुष एकल खिताब जीतने वाले 24 वर्षीय सिनर के लिए यह उपलब्धि बेहद खास है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सेंटर कोर्ट पर पहला मुकाबला खेलना उनके लिए रोमांचकारी क्षण होगा। उनके अनुसार विंबलडन का वातावरण दुनिया के किसी भी अन्य टेनिस कोर्ट से अलग है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था

कि एक दिन चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में वही सेंटर कोर्ट पर उतरेंगे।

महिला वर्ग में गत चैंपियन इगा स्वियातेक दूसरे दिन सेंटर कोर्ट पर अभियान की शुरुआत करेंगी। पिछले वर्ष खिताब जीतकर वे विंबलडन महिला एकल चैंपियन बनने वाली पहली पोलिश खिलाड़ी बनी थीं।

स्वियातेक ने कहा कि विंबलडन ट्राफी जीतना उनके लिए शब्दों से परे अनुभव था। उन्होंने बताया कि घास के कोर्ट पर अपने खेल को ढालने के लिए उन्होंने लंबे समय तक मेहनत की और आक्रामक खेल शैली अपनाने पर विशेष ध्यान दिया। उनके अनुसार विंबलडन के समृद्ध इतिहास का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। विंबलडन के इतिहास में कई महान खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है। ब्योर्न बोर्ग, क्रिस एवर्ट, स्टेफन एडबर्ग, पैट राफ्टर और रोजर फेडरर जैसे दिग्गजों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए टेनिस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पांच बार लगातार विंबलडन चैंपियन रहे ब्योर्न बोर्ग ने अपने पहले खिताब की याद ताजा करते हुए कहा कि ग्रस कोर्ट पर सफल होने के लिए उन्हें अपने खेल में बदलाव करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि सही लय और रणनीति मिलने के बाद ही वे इस सतह पर सहज महसूस करने लगे और यही उनकी सफलता का आधार बना। इस बार भी कई युवा सितारे पहली बार विंबलडन खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे। महिला वर्ग में हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने वाली मीरा आंद्रेएवा, बेलिंडा बेनचिच, कोको गाफ, मारिया सक्कारी और किनवेन झेंग प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। पुरुष वर्ग में जोआओ फोन्सेका, टेलर फ्रिट्ज, बेन शेल्टन और स्टेफानोस सित्सिपास जैसे खिलाड़ी खिताब की दौड़ में नजर आएंगे। 149 वर्षों के गौरवशाली इतिहास वाले विंबलडन में इस बार भी दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों की निगाहें सेंटर कोर्ट पर टिकी रहेंगी, जहां एक बार फिर नए अध्याय लिखे जाएंगे।

सही रोडमैप तैयार करें...

दिल में हजारों सपने और मन में जीत का जज्बा लिए युवा निकल पड़ते हैं अपने ड्रीम करियर की ओर। मगर कई बार सही रोडमैप तैयार न होने से उन्हें मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई होती है। संबंधित कोर्स आदि करने के बाद भी कामयाबी मिलने वालों का प्रतिशत बहुत कम देखा गया है। अधिकतर युवा पढ़ाई के दौरान ही अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं, मगर सही रोडमैप तैयार न होने के कारण वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और हताश हो जाते हैं। आइए जानते हैं ड्रीम करियर तक पहुंचने का क्या हो रास्ता।

खुद को परखें

सभी व्यक्ति एक जैसे नही होते। सबकी ताकत, कमजोरी, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और सपने सभी कुछ एक–दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। साथ ही हर किसी में कोई न कोई खूबी जरूर होती है, जो उस व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग बनाती है। सबसे पहले अपनी इस खूबी को पहचानिए। इससे खुद की पहचान में मदद मिलेगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपने बाकी साथियों के मुकाबले किस स्तर पर हैं? इसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस में सुधार के लिए सही तरीके अपना सकेंगे। अपनी ताकत के ईद-गिर्द ही अपना करियर बनाइए। इससे आप न सिर्फ अपने करियर में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेंगे, बल्कि आपका आंतरिक विकास भी होगा और आप हमेशा खुश रह सकेंगे।

व्यक्तित्व को पहचानें

ऐसा काम न चुनें, जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप न हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो मार्केटिंग के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत सुनहरा नहीं होगा। हम जिस चीज से संतुष्ट होते हैं और जो काम करने में सहजता महसूस करते हैं, वही बेहतर रूप से कर सकते हैं। जिस काम को हम रुचि के साथ आनंद लेकर करते हैं, उस काम में सफलता मिलना आसान होता है, लेकिन जो काम हमें असहज या कठिन लगते हैं, जिन्हें करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, उनमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है।

लक्ष्य तय करें

एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए गए सर्वे में यह बात निकल कर सामने आई है कि किसी भी करियर के प्रति रुझान उम्र के साथ-साथ बदलता है। वही लोग अंत तक एक करियर से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, जिन्होंने लक्ष्य तय किया हुआ था और उन्हें अपने करियर से प्यार था। पहली ही नौकरी का चयन अगर सही नहीं हुआ तो करियर में तरक्की की राहें मुश्किल हो सकती हैं। ऐसे में बार-बार नौकरी बदलने में आपका कीमती वक्त बर्बाद होगा। यह पहले से तय कर लें कि आपको किस क्षेत्र में करियर बनाना है या किन कंपनियों में काम करना चाहते हैं। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने नई रिपोर्ट में आंकड़ों के आधार पर 20 सबसे अच्छी नौकरियों की एक सूची पेश की है। इनमें इंजीनियर और विश्लेषक की नौकरियों को सबसे ऊपर रखा गया है। आंकड़ों का परीक्षण ग्लासडोर ने किया है।

क्षमताएं बढ़ाएं

ग्लासडोर डॉट कॉम वेबसाइट द्वारा करवाए गए सर्वे के मुताबिक जिन 63 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्किल्स को बढ़ाने पर काम किया, उन्हें बेहतर पदोन्नति के साथ अच्छी सैलरी भी मिली। सर्वे में 74 प्रतिशत ने माना कि उन्हें खुद को आगे बढ़ाने के लिए स्किल्स सीखनी होंगी। 48 प्रतिशत कर्मचारियों के मुताबिक उनकी डिग्री उनके काम के साथ कहीं मेल नहीं खाती यानी इससे साफ हो गया कि शुरुआत में भले ही आप अपनी डिग्री की बदौलत कोई नौकरी पा लेते हैं, मगर उसमें टिके रहने व तरक्की पाने के लिए आपको अपनी मौजूदा क्षमताओं में इजाफा करना होगा। उन स्किल्स को पहचान कर सीखना होगा, जो आपके काम में सहायक हैं।

पाएं कार्यानुभव

किसी कंपनी में की गई इंटर्नशिप आपको आपके ड्रीम करियर तक पहुंचने में सहायक हो सकती है। इंटर्नशिप के दौरान आप क्लास रूम की थ्योरी क्लासेज से निकल कर जॉब मार्केट और पेशवर कार्यों की दुनिया से परिचित होते हैं। आपने जो शिक्षा हासिल की है, उसका वास्तविक प्रयोग कैसे करना है और आपकी शिक्षा आपके ड्रीम करियर में रास्ता बनाने में किस हद तक सहायक होगी, इसे इंटर्नशिप के दौरान परखा और जांचा जा सकता है।

रेज्यूमे हो दमदार

किसी भी कंपनी में अपना रेज्यूमे भेजने से पहले यह निश्चित कर लें कि इसमें कहीं कोई भाषाई अशुद्धि तो नहीं है, कोई योग्यता बढ़ा-चढ़ा कर तो नहीं लिखी गई है। इसके बाद ध्यान दें कि उसका डिजाइन, फॉन्ट साइज, आकर्षक हो, ताकि पढ़ते समय बोरियत न हो। जो भी कहना चाहते हैं, वह संक्षेप में प्रभावी ढंग से लिखा होना चाहिए।

रिसर्च करें

जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारियां एकत्र करें। उस क्षेत्र में काम कैसे होता है, काम करने की शैली कैसी है, वेतन कितना मिलता है, आने वाले समय में उस क्षेत्र में विकास की क्या संभावनाएं हैं, सरकार की नीति सेक्टर के लिए क्या है, क्षेत्र में काम करने के दौरान किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

क्षमता और रुचि का रखें ध्यान...

12वीं के बाद करियर की दिशा को लेकर विद्यार्थियों के मन में कई सवाल होते हैं। मसलन- कौन-सी स्ट्रीम चुनें, प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लें या पारंपरिक डिग्री हासिल करें आदि। काउंसलर की मानें तो कैरियर की दिशा चुनते वक्त आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-क्षमता और रुचि। यदि आप इन बातों की तह तक पहुंच गए, तो आप अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। नजर डालते हैं बारहवीं के बाद के उन प्रमुख कैरियर विकल्पों पर, जिनमें से कोई एक क्षेत्र चुन कर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपने क्षेत्र का चुनाव अपनी क्षमता और रुचि का आकलन करने के बाद किया हो।

चार्टर्ड अकाउंटेंसी

जो छात्र 10+2 में वाणिज्य लेते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी की मांग कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों में है। अंतरराष्ट्रीय अवसरों के कारण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी युवाओं के लिए अग्रिम कैरियर विकल्प बन गया है। द इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के अधीन पंजीकृत संस्था है, को भारत में इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाने का एकाधिकार प्राप्त है। विशेष जानकारी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आइसीएआइ डॉट ओआरजी पर संपर्क करें।

कंपनी सेक्रेटरीशिप

वाणिज्य से 10+2 पूरा करने वाले छात्रों का एक बड़ा वर्ग कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है। आज हर उस कंपनी में, जिसका पेड-अप पूंजी 1 करोड़ से अधिक है, एक कंपनी सेक्रेटरी होना अनिवार्य है। तीन स्तरों में होने वाले इस पाठ्यक्रम सह परीक्षा की विस्तृत जानकारी के लिए आपइंस्टीट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आइसीएस आइ डॉट इडीयू पर संपर्क करें।

कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट

फाइनेंस के क्षेत्र में एक नया क्षेत्र उभर कर आया है, जिसे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरीशिप की तरह तीन स्तरों- फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा को उतीर्ण कर कॉस्ट अकाउंटेंट की योग्यता प्राप्त कर सकता है। कॉस्टअकाउंटेंट किसी कंपनी का वह पदाधिकारी होता है, जिसे अपनी तकनीकी दक्षता से कंपनी की पूंजी व लागत का उचित इस्तेमाल करना होता है। विस्तृत जानकारी के लिए आपइंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आइसीएमएआइ डॉट इन पर संपर्क करें।

लॉ का क्षेत्र

वाणिज्य से बारहवीं के बाद छात्रों का एक बड़ा तबका लॉ के क्षेत्र में जाता है. 10+2 के बाद 5 वर्षीयलॉइंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम पूरा करकानून के क्षेत्र में कैरियर को एक नई दिशा दी जा सकती है। पहले इस इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम में केवल बीएएलएलबी पाठ्यक्रम ही होता था। परंतु समय की मांग को देखते हुए बीएएलएलबी के अतिरिक्त व्यापार प्रबंधन की चाह रखने वाले छात्रों के लिए बीबीएएलएलबी, विज्ञान के छात्रों के लिए बीएससीएलएलबी या कॉमर्स के छात्रों के लिए बीकॉमएलएलबी पाठ्यक्रमों की भी घोषणा कर दी गयी है। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आपको एक विशेष प्रवेश जांच परीक्षा देनी होगी, जिसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट कहा जाता है। इस प्रवेश जांच परीक्षा के माध्यम से आपको देश के प्रतिष्ठित लॉ विश्वविद्यालय में दाखिले का अवसर प्राप्त होगा। विशेष जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें।

बैंकिंग का क्षेत्र

यदि हम यह कहें कि आनेवाले कुछ वर्ष बैंकिंग के क्षेत्र में नई नौकरियों की चाह रखने वाले छात्रों के नाम होंगे, तो कुछ गलत न होगा। आगामी कुछ वर्षों में लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए बैंकिंग सेक्टर के दरवाजे खुले रहेंगे। यदि आप 10+2 के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्लर्क लेवल के लिए आवेदन करें। हालांकि कई बैंकों में अब क्लर्क के लिए भी स्नातक आवश्यक योग्यता के रूप में मांगी जाती है, परंतु कुछ विकल्प अभी भी 10+2 के बाद इस पद के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वाणिज्य से स्नातक करें और प्रवेश जांच परीक्षा में बैठने की रणनीति बनायें। बैंकों की रिक्तियों की अधिसूचना निरंतर अखबारों में निकलती रहती हैं।

बिजनेस मैनेजमेंट

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने जहां एक ओर कॉरपोरेट दुनिया को नया आयाम प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर बिजनेस मैनेजरों की भारी मांग ने युवाओं के लिए कैरियर द्वार खोल दिया।10+2 वाणिज्य के बाद 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आपको बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में प्रवेश दिला सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों को अलग-अलग विश्वविद्यालय में कई बार अलग-अलग नाम से जाना जाता है, परंतु इनके कोर्स कंटेंट लगभग एक जैसे होते हैं। कहीं इसे बीबीए यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, तो कहीं इसे बीबीएमयानी बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट कहा जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय मे इसे बैचलर इन बिजनेस स्टडीज का नाम दिया गया है। इन पाठ्यक्रमों में स्नातक करने के बाद किसी अच्छे संस्थान से एमबीए करने वाले छात्रों को पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती।

पत्रकारिता का क्षेत्र

एक समय था जब इस विषय को हिंदी या अंग्रेजी विभाग के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चकाचौंध ने युवाओं के एक बड़े वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 10+2 वाणिज्य के बाद 3 वर्षीय बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या बीए (जेएमसी) जैसा पाठ्यक्रम आपको मीडिया के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दे सकता है, परंतु इस क्षेत्र में संघर्ष है, आपके स्थापित होने की समय सीमा भी निश्चित नहीं है। इस जोखिम को ध्यान में रखकर ही आप इस क्षेत्र में जाने की योजना बनायें। इस क्षेत्र में सफलता के लिए आपकी भाषा पर मजबूत पकड़ बेहद जरूरी है, चाहे बात प्रिंट मीडिया की हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। वाणिज्य से पढाई करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देखने वाले छात्र बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन इकनोमी, सीएनबीसी आवाज जैसे चैनलों और अखबारों में रोजगार खोज सकते हैं। इन चैनलों में वाणिज्य के जानकार को आर्थिक या बिजनेस पेज या प्रोग्राम का उत्तरदाई बनाया जाता है।

कंप्यूटर साइंस

एक समय था जब केवल गणित के छात्र ही इस क्षेत्र में प्रवेश करते थे। समय के साथ बढ़ती मांग को देखते हुए कई विश्वविद्यालय वाणिज्य या आर्ट्स के छात्र को भी इस क्षेत्र में प्रवेश देते हैं। बीसीए यानी बैचलर इन कंप्यूटर अप्लीकेशन के लिए 10+2 पर आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसी प्रकार के अन्य पाठ्यक्रम जैसे बीएससी (कंप्यूटर साइंस) या बीएससी (आइटी) में प्रवेश के लिए ज्यादातर विश्वविद्यालय 10+2 में गणित मांगते हैं। रुचि कंप्यूटर साइंस में है, तो निःसंकोच बीसीए पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम रेग्युलर हो,अन्यथा पूरा व्यावहारिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा, जो क्षेत्र में सफल होने का आधार है।

मेडिकल

बायो के साथ 10+2 लेने वाले छात्रों का पहला कैरियर विकल्प मेडिकल होता है। एक बात समझना आवश्यक है। कई छात्र मेडिकल में कैरियर बनाने की चाह में चीन, रूस इत्यादि से मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं। ध्यान रहे, भारत में केवल वही मेडिकल डिग्री मान्य है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्य है। यदि आप देश से बाहर से कोई मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं, तो आपको पुनः मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, अन्यथा आपकी डिग्री अवैध हो जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए सीबीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके आधार पर सरकारी-पोषित व निजी मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया जा सकता है।

डेंटिस्ट्री

बायो के साथ 10+2 उतीर्ण करने वाले छात्रों के लिए डेंटिस्ट्री (दांतों का डॉक्टर) भी एक उत्तम कैरियर विकल्प है। चार वर्षीय बैचलर इन डेंटल सर्जरी करने के बाद यदि आप इसमें मास्टर्स कर लें तो फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मान्य संस्थानों की अद्यतन जानकारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध है। निजी संस्थानों के अतिरिक्त सरकारी संस्थानों में बीडीएस में दाखिले के लिए भी सीबीएससी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को उतीर्ण करना आवश्यक है।

बायोटेक्नोलॉजी

रिसर्च और तकनीक से यदि आपका लगाव हो, तो बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र आपको एक स्थायी कैरियर विकल्प दे सकता है। फार्मा कंपनियों में निरंतर बायो तकनीक विशेषज्ञों के लिए रिक्तियां निकलती रहती हैं। इस विषय को लेकर दो प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं- तीन वर्षीय बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और चार वर्षीय बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। कैरियर के लिहाज से इनमें से किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद एमबीए करना बेहतर होगा, ताकि आपको तकनीकी ज्ञान के साथ साथ प्रबंधन कौशल भी आ सके।

अल्टरनेटिव मेडिसिन

एमबीबीएस के अतिरिक्त होमियोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद जैसे अन्य कैरियर विकल्प भी हैं, जो आपको एक डॉक्टर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन होमियोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी के अतिरिक्त नेचुरोपैथी, योग, फिजियोथेरपी जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनको आप अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं।

नर्सिंग का क्षेत्र

नर्सिंग का क्षेत्र उन चुनिंदा क्षेत्रों में है, जिन में कभी भी रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे। इस क्षेत्र में कई पाठ्यक्रम हैं, जैसे एक वर्षीय ऑक्जिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी यानी एएनएम से लेकर चार वर्षीय बीएससी नर्सिंग तक। मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची काउंसिल की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडियन नर्सिंग काउंसिल डॉट ओआरजी पर उपलब्ध हैं।

इंडियन आर्मी

देश के युवाओं का एक तबका ऐसा भी है, जो अपने रोजगार के साथ-साथ देश की सेवा भी करना चाहता है। तो आर्ट्स के छात्र के रूप में आपके लिए यहां भी इंडियन आर्मी के दरवाजे खुले हुए हैं। जब आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हों, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस में प्रवेश की योजना बनाएं।

प्रेग्नेंसी में कैसा भोजन खाना करना चाहिए?

आपको जरूरत है अपने आहार का ध्यान रखने की। क्या खाना है और क्या नहीं। क्या मैं नॉन-वेज खाऊं या नहीं। क्या मुझे पूरी तरह वेजिटेरियन रहना चाहिए। इसे लेकर कई महिलाएं दुविधा में रहती हैं। मांसाहारी भोजन में सब्जियों और फलों की तुलना में ज्यादा आयरन होता है। यदि आपको नॉन वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो यह आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा। यदि आपके शरीर में आयरन पहले से ही उचित मात्रा में मौजूद है तो आप नॉनवेज का इस्तेमाल 10 से 11 हफ्तों में भी कर सकती हैं।

नॉनवेज खाने में आपके लिए मछली का सेवन सबसे अच्छा रहेगा। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। हालांकि ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप भोजन में अलसी के बीजों का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए मछली के सेवन से बेहतर कुछ नहीं। गर्भावस्था के दौरान आपको आम दिनों की ही तरह ही हेल्दी खाना खाना चाहिए। महिलाएं अपनी और गर्भस्थ शिशु की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने से खुशी का अनुभव करती है। इसलिए नॉन वेज उन सभी जरूरतों को पूरा करता है जो आपको और आपके नन्हें मेहमान के लिए जरूरी हैं। इस दौरान आपकी दिनभर की दिनचर्या में ब्रेकफास्ट, पास्ता, चावल और रोटी सभी कुछ होना चाहिए। यदि आप नॉनवेज हैं तो आपको प्रोटीन युक्त फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको खाने से संबंधित सभी चीजें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नियमित अंतराल पर लेनी चाहिए। एक बार में ज्यादा खाना आपको नुकसान दे सकता है। ऐसी कुछ नॉन वेज डिश जिन्हें आप प्रोटीन और आयरन के लिए यूज कर सकती है।

चिकन स्वीट कोर्न सूप: चिकन स्वीट कोर्न सूप प्रोटीन के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसे तैयार करने के लिए आपको 250 ग्राम बोन लैस चिकन, आधा कप स्वीट कोर्न क्रीम की जरूरत पड़ेगी।

स्टीम्ड लैमन फिश सैलड: स्टीम्ड लैमन फिश सैलड में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा के साथ ही आयरन और विटामिन सी होता है। यह गर्भावस्था के दौरान आपके और आपके यहां आने वाले नन्हें मेहमान के लिए फायदेमंद रहेगा। इसे तैयार करने के लिए 300 ग्राम बिना हड्डी वाली मछली, 2 हरी मिर्च, नींबू का रस और धनिया पत्ती चाहिए।

फिश फिंगर: फिश फिंगर को आप अपनी दिनचर्या में स्नैक्स की तरह यूज कर सकती हैं। इसमें न केवल प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा है बल्कि विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ ही कैल्शियम भी है। इसे तैयार करने के लिए आपको 300 ग्राम बोन लैस फिश के पीस, धनिया पत्ती, नींबू का रस, जीरा पाउडर और फैट किया हुआ छोटे अंडे की जरूरत होगी।

चिकन टिक्का चाट: चिकन टिक्का चाट को भी आप फिश फिंगर की ही तरह बतौर स्नैक्स यूज कर सकती हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और विटामिन सी की भरपूर मात्रा है।

स्पाइसी स्पागेटी और मीटबॉल्स: इसका इस्तेमाल आप अपने खाने के दौरान कर सकती हैं। स्पाइसी स्पागेटी और मीटबॉल्स का सेवन आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी सब कुछ देगा। इसे तैयार करने केक लिए 150 ग्राम स्पागेटी, 300 ग्राम मटन, मशरूम, प्याज, अदरक, दूध, अंडा और मिर्ची पाउडर की जरूरत होगी।

चिकन पीस पुलाव: चिकन पीस पुलाव में विटामिन ए, सी और के साथ ही फोलेट भी उचित मात्रा में होता है। टेस्टी चिकन पीस पुलाव का सेवन आप अपने भोजन में करें।

रेसिपी

ब्रेड कोफ्ता करी

सामग्री

ब्रेड कोफ्ते के लिए: 6 ताजे ब्रेड के स्लाईस, 5 स्पून ताजा दही, 2 स्पून मैदा, 2 स्पून बेसन, 2 स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 स्पून कटी हुई हरी मिर्च, एक चुटकी बेकिंग सोडा **अन्य सामग्री:** 1 कप लौकी के टुकड़े, 3 स्पून तेल, 1/2 कप उबले और छिले हुए छोटे आलू, आधे कटे हुए, 1/2 कप कसा हुआ प्याज, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून धनिया-जीरा पाउडर, 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 स्पून ताजा दही, 3/4 कप ताजा टमाटर का पल्प, 1/2 कप उबले हुए हरे मटर, **सजाने के लिए:** 1 स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया

विधि

ब्रेड कोफ्ते के लिए: ब्रेड स्लाईस के कीनारे निकाल लें। ब्रेड स्लाईस को बाउल मे रखकर चुरा कर लें, दही, मैदा, बेसन, धनिया, हरी मिर्च, बेकिंग सोडा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को 20 बराबर भाग मे बांटकर प्रत्येक भाग के गोल आकार बना लें। कढ़ाई मे तेल गरम करें और एक बार मे थोड़े कोफ्ते डालकर, उनके सभी तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। तेल सोखने वाले कागज ने निकालकर एक तरफ रख दें। **आगे बढ़ने की विधि:** एक गहरी नॉन-स्टिक कढ़ाई में लौकी और 1 कप पानी मिलाकर, बीच-बीच मे हिलाते हुए, मध्यम आंच पर लौकी के नरम होने तक या 8-10 मिनट के लिए पका लें। मिश्रण को पुरी तरह ठंडा कर मिक्सर मे पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें। एक तरफ रख दें। गहरी नॉन-स्टिक कढ़ाई में 2 टेबल-स्पून तेल गरम करें और आलू डालकर मध्यम आंच पर 2-3 मिनट या आलू के सुनहरे होने तक भून लें। छानकर एक तरफ रख दें। उसी कढ़ाई में, बचा हुआ 1 टेबल-स्पून तेल गरम करें, प्याज डालकर मध्यम आंच पर 2-3 मिनट या प्याज के पारदर्शी होने तक भून लें। हल्दी, धनिया-जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल-स्पून पानी डालकर मध्यम आंच पर 1 मिनट तक पकाएं। ताजा दही और टमाटर का पल्प डालकर अच्छी तरह मिलाएं और बीच-बीच मे हिलाते हुए, मध्यम आंच पर 1-2 मिनट के लिए पकाएं। लौकी का पेस्ट, 1/2 कप पानी, नमक, हरे मटर और भुने हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और बीच-बीच मे हिलाते हुए, मध्यम आंच पर 2-3 मिनट के लिए पकाएं। परोसने के तुरंत पहले ब्रेड कोफ्ता डालें और हल्के हाथों से मिलाकर मध्यम आंच पर 1-2 मिनट तक पकाएं। धनिया से सजाकर गरमा गरम परोसें।

हान्डी खिचड़ी

सामग्री

3/4 कप चावल, 15 मिनट के लिए भिगोकर छाने हुए, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 स्पून धनिया-जीरा पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, 1 स्पून लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादअनुसार, 1/2 कप छिले हुए आलू के टुकड़े, 1/4 कप हरे मटर, 1/2 कप फूलगोभी के फूल, 2 स्पून तेल, 2 इलायची, 25 मिलीमीटर दालचीनी का टुकड़ा, **परोसने के लिए:** छाछ, पापड़

विधि

धनिया, प्याज, धनिया-जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और नमक को एक गहरे बाउल में अच्छी तरह मिला लें। आलू, हरे मटर, फूलगोभी, तेल, चावल, इलायची और दालचीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को हान्डी मे डालकर, 11/2 कप गरम पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। ढक्कन से ढक कर, धीमी आंच पर 25-30 मिनट के लिए, बीच-बीच में हिलाते हुए पका लें। छाछ और पापड़ के साथ तुरंत परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**